HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-31 मार्च, 2019

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 17/ पृष्ठ: 16

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

मूल्य: ₹ 25/-

THE RIEV TIMES
OFFICIAL MEDIA PARTNER
Krishi & Wellness
INDIA 2019 EXPO
Linking Agriculture, Food & Wellness
06-07-08 August 2019
Pragati Maidan, New Delhi, India

मौसम का हाल

मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मौसम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार करवट बदलेगा। आगामी सप्ताह में मैदानी, कम ऊंचाई वाले और चोटियों पर कहीं–कहीं शुष्क तो कहीं वर्षा एवं गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 19 मार्च से 21 मार्च तक मौसम फिर से करवट बदलेगा और गरज के साथ छींटे व बारिश व हल्की बर्फ पड़ने की संभावना है। 22 मार्च से मौसम शुष्क रहेगा।

होली केवल रंगो का त्यौहार नहीं है, यह रिश्तों, भाईचारा एवं संस्कृति की पहचान का प्रतीक है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... हिमाचल समाचार
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श,जाने कानून व अन्य
- पृष्ठ 8...संपादकीय: five years of Modi regime
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...शिक्षा लोन योजना
- पृष्ठ 15...हिमाचल सरकार की योजनाएं
- पृष्ठ 16...मिशन रीव में रोज़गार के अवसर

चुनावी महासमर का बजा बिगुल

हिमाचल में 77 दिन तक रहेगी आचार संहिता

हिमाचल भी रंगा चुनावी रंग में

हेम राज चौहान

आख़िर लोकतंत्र का महापर्व आरम्भ हो गया है। एक नए लोकतंत्र की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का आरंभिक चरण का उद्घोष हो चुका है। पांच वर्षों के बाद ये पर्व देश के भाग्य को तय करता है। हिमाचल प्रदेश में इस बार 77 दिन तक हरक्षण चुनावी हलचल बनी रहेगी। हिमाचल में 19 मई को लोग अपना मत वीपीपीटी मशीन में बंद करेंगे जिसका नतीज़ा 23 मई को आना है। हालांकि भारत में चुनावों के मौसम सदाबहार है और गाहे–बगाहे कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन हिमाचल में चुनावों का अपना ही केज है। हालांकि लोकसभा के लिए यहां से कुल 4 ही सीट हैं फिर भी लोगों में चुनावों को लेकर खासा उत्साह है।

राजनैतिक पार्टियों ने भी गोटियां फेंकनी शुरु कर दी है। प्रत्याशियों को लेकर उठापठक का दौर शुरु हो चुका है तथा इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग पुराने साथियों पर दांव चलने का मन बना लिया है। जबकि कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि चारों सीटों पर उनकी जीत होगी तो वहीं भाजपा मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ पार पाना चाहता है।

हिमाचल में इस बार 77 दिनों तक आचार संहिता रहेगी। यानि एक लंबा इंतज़ार न केवल चुनावों और नतीज़ों का बल्कि नए कार्य आरंभ करने में भी। विकास के कार्यो की रफ्तार पर विराम लग जाएगा।

नगर निगम शिमला स्थान उपलब्ध करवाने में करेगा सहयोग...महापौर

शिमला शहर में भी आईआईआरडी खोलेगा जनऔषधि केन्द्र

हेम राज चौहान

जनऔषधि दिवस के अवसर पर आईआईआरडी शनान में हुए भव्य कार्यक्रम में महापौर शिमला कुसुम सदरेट ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने शनान में चलाए जा रहे जन औषधि केन्द्र की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को इस केन्द्र के खुलने से बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा से आग्रह किया कि आईआईआरडी शिमला शहर में भी इस प्रकार के केन्द्र खोलने की पहल करे जिसके लिए स्थान की उपलब्धता नगर निगम शिमला करवाऐगा। इस अवसर पर एक जागरुकता रैली भी निकाली गई।

शेष पेज 3 पर...

लोकसभा चुनावो में विभिन्न परीक्षाओं की तिथि बदली

एचएएस समेत कई अहम पदों की परीक्षाएं चुनावों के बाद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनावों के चलते नए विकास कार्यों पर ब्रेक लगना लाजमी हैं लेकिन इस बार होने वाले चुनावों का असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं के लिए अप्रैल में परीक्षाएं होनी थी लेकिन आयोग ने अधिसूचना जारी कर अब एचएएस परीक्षाओं की तिथि बदल दी है। हिमाचल में 19 मई को चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए आयोग ने एचएएस की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 13 अप्रैल को आयोजित न करने का निर्णय लिया है। अब यह परीक्षा आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 26 मई को आयोजित की जाएगी।

लोक सेवा आयोग की सचिव एकता कपटा ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की उन्होंने सभी आवेदकों से आग्रह किया कि यदि किसी तरह की सूचना चाहिए तो वे टोल फ्री नंबर 1800–180–8004 पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर सुबह 10 से सांय पांच बजे तक डायल कर सकेंगे।

एचआरटीसी ने भी टाली भर्ती

हिमाचल पथ परिवहन में करीब 100 हजार चालकों परिचालकों की भर्ती की जानी थी। लेकिन चुनावों के चलते अब इसे टाल दिया गया है। एचआरटी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। इसलिए प्रबंधन ने इस बार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। भर्ती करने के लिए एचआरटीसी बीओडी की बैठक से मंजूरी मिल गई लेकिन इससे पहले कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होती, आचार संहिता लग गई।

मेडीकल एजूकेशन में विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे

प्रदेश में मेडीकल एजूकेशन विभाग में हिमाचल लोक सेवा आयोग की ओर से करीब 34 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 9 मार्च को आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापन के मुताबिक मेडीकल एजूकेशन विभाग में प्रवक्ता के 14 और सहायक प्रवक्ता के 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च तय की गई है।

स्वाइन फ्लू से हिमाचल में 37 लोगों की मौत, 300 मामले पॉजिटिव

अब फोटो और संपर्क नंबर के साथ तैयार होगी पीड़ितों की सूची

लगातार मामले सामने आने पर विभाग ने जारी की एडवाइजरी

अंजना ठाकुर

हिमाचल में सर्दियां यहां के लोगों के लिए आफत लेकर आती है। बर्फबारी से जीवन थम जाता है तो कई संक्रामक रोग जीवन ही समाप्त कर देते हैं। स्वाइन फ्लू भी इन्हीं संक्रामक रोगों में से एक है। इस रोग के चलते हिमाचल में इन सर्दियों में 37 लोगों की मौता हो चुकी है ज बकि 300 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ विभाग की ओर से 12 मार्च तक जो डेटा विभिन्न जिलों से एकत्र किया गया है उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू का सबसे अधिक कहर जिला शिमला में है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12 मार्च तक जिला शिमला से 91 मामले स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। ज बकि 4 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से जिला शिमला में हुई है। गौर हो कि जनवरी माह में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए थे और अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा था।

बहरहाल शिमला के बाद दूसरे नंबर पर जिला कांगड़ा है। कांगड़ा से अभी तक 79 मामले सामने आए हैं और यहां पर 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह बिलासपुर समेत अन्य जिलों से 300 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बार सर्दियों लंबी होने से स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बरकरार है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से जारी एडवाइजरी में स्वाइन फ्लू को लेकर तमार एतिहात बरतने के साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि स्वाइन फ्लू से पीड़ितों का अलग से डेटा तैयार किया जाए। निर्देशों के मुताबिक पीड़ितों की सूची तैयार करते हुए अब उनके फोटो और संपर्क नंबर भी सूची में लगाना होगा। ताकि आसानी से फॉलोअप किया जा सके और आसपास के क्षेत्रों में संभावित खतरे से निपटा जा सके। किसी भी तरह के संदिग्ध का जल्द टेस्ट कराने की सलाह दी गई और टेस्ट के लिए सैंपल आईजीएमसी, टांडा, सीआरआई कसौली, सोलन और मंडी भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी चिकित्सा अधिकारियसों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में ओसेल्टामिविर (स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए दी जाने वाली दवाई) का उचित प्रबंध करने को कहा गया है। इसके साथ ही संभावित मामलों में लैब रिपोर्ट का इंतजार न करते हुए 48 घंटों के अंदर मरीज को दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निजी क्लीनिकों में भी इस दवा के स्टॉक को मॉनीटर करने को कहा गया है ताकि समय पड़ने पर दवाई की आपूर्ति निश्चित हो सके। सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध वेंटीलेटर को वर्किंग कंडीशन में रखना भी चिकित्सा अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही अन्य जरूरी एतिहात बरतने और लोगों को स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे और इससे बचाव करने को लेकर लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश जारी हुए हैं।

द रीव क्लीनिक शिमला एचओडी डाक्टर केआर शांडिल के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक संक्रामक वायरल संक्रमण है, जो सूअरों से मनुष्यों तक फैलता है। यद्यपि सूअर संक्रमण का मुख्य स्रोत हैं, एक बार यह मनुष्यों तक पहुंचने के बाद, यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। यह बीमारी साल 2009 में एक महामारी की तरह फैल गयी थी, जब पहली बार इंसानों को संक्रमित किया गया था।

यह रोग छींक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलता है। श्वसन पथ संक्रमित होने के कारण एक व्यक्ति खांसी, बुखार, नाक स्राव और सिरदर्द से पीड़ित होता है।

Social Security and Emergency Service Division renamed as Disaster Risk Reduction (DRR) and Social Security Division

The RIEV Times

Mission RIEV Management took a decision to rename the Social Security and Emergency Service Division as Disaster Risk Reduction (DRR) and Social Security Service Division as a number of services being delivered in disaster like situations by the Mission including general awakening and capacity building of the rural population, the disaster mitigation and risk reduction had got prominence. The recent measures on mass anti-rabies vaccination in one of the villages of Chamba District of Himachal Pradesh, after milk consumption of a dog-bit cow who later died due to rabies, had also invited due attentions of the authorities who appreciated IIRDs endeavors under Mission RIEV in this direction.

जम्मू में हुए विस्फोट के बाद हिमाचल में अलर्ट, सीमा क्षेत्र में पुलिस सतर्क

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जम्मू में बस स्टैंड पर बम धमाके के बाद हिमाचल में भी पुलिस सतर्क हो गई है । चंबा जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है । चंबा के साथ लगती जम्मू–कश्मीर की 216 किलोमीटर लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। चंबा–जम्मू सीमा पर सेवा ब्रिज पर वाहनों को जांच के बाद ही आगे भेजा जा रहा है । सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त की जा रही है। साथ सटे जिला कांगड़ा में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हवाई अड्डे व बांध क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है।

उधर, एसपी चंबा डॉ. मोनिका का कहना है जम्मू–चंबा की सीमा पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सीमा पर नजर बनाए हुए है। सीमा पर किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। पुलिस जवानों ने जम्मू–कश्मीर से सटे चंबा बॉर्डर की नाकेबंदी कर सर्च अभियान भी चलाया है । चंबा बॉर्डर पर 13 चौकियां स्थापित की हैं। बॉर्डर को संवेदनशील इसलिए माना जाता है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आदि की सक्रियता है। जम्मू–कश्मीर राज्य की सीमा जिले के सलूणी उपमंडल के लंगेरा, चुराह उपमंडल के सतरुंडी तथा खैरी के साथ लगती है। इसके अलावा पंजाब के साथ भी तुन्नुहट्टी के साथ चंबा की सीमा लगती है।

प्रशासन की अनूठी पहल, पोस्टकार्ड के जरिये जागरुक होंगे नए मतदाता

द रीव टाइम्स ब्यूरा

21वीं सदी में सोशल मीडिया प्रचार–प्रसार का मुख्य साधन बन चुका है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसके हाथ में स्मार्ट फोन न हो, लेकिन नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सिरमौर जिला प्रशासन ने डाक भेजकर जागरूकता की अनूठी पहल की है।

इसमें डाकिया घर–घर जाकर लोगों को पोस्टकार्ड वितरित करेगा। मतदाताओं से वोट डालने की अपील की जाएगी । पोस्टकार्ड पर 'जागरूक मतदाता लोकतंत्र का भाग्य विधाता', क्या आप 18 वर्ष के हो चुके हैं? यदि हां तो अपना वोट अवश्य बनाएं संदेश लिखा गया है।

हिमाचल पुलिस में भर्ती होंगे 1063 कांस्टेबल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव के एलान से पहले प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल पुलिस में कुछ 1063 कांस्टेबलों की भर्ती होगी । सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

कांस्टेबल भर्ती के लिए पहली बार हिमाचल पुलिस ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। अभ्यर्थी 30 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। कांस्टेबल बनने के लिए लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अलावा 15 अंकों का साक्षात्कार होगा।

पुरुषों के लिए कांस्टेबल के 720 पद, महिलाओं के 213 और चालक कांस्टेबलों के लिए 130 पद रखे गए हैं। सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में 234 पद जबकि सबसे कम पांच पद लाहौल स्पीति में भरे जाएंगे ।

अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया हर जिले में अलग–अलग समय पर होगी, जिसकी अधिसूचना अलग से होगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा में श्रेणीवार लंबाई

और पुरुष आवेदकों की छाती की नपाई के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए हैं।

उम्र की अधिकतम और न्यूनतम उम्र तय करने के लिए एक जनवरी 2019 को कट ऑफ डेट रखा गया है। खास बात यह है कि बारहवीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। इंटरव्यू के समय उन्हें परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 6.30 मिनट में 1500 मीटर रेस और महिला आवेदकों को 4.5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी ।

हिमाचल में 88 हजार से ज्यादा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में 19 मई को लोकसभा की चार सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए जाने है। इसके लिए प्रदेश चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के दौरान 88 हजार से ज्यादा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 48 हजार 211 पुरुष, 39 हजार 889 महिला और 27 थर्ड जेंडर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार करें और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अथवा पार्टी कार्यकर्ता की ओर से लोगों को घूस आदि दिए जाने पर कार्रवाई करने के लिए जागरूक किया जाएगा। हिमाचल के चुनावों में कुल 51 लाख 59 हजार मतदाता भाग लेंगे। इनमें 26 लाख 45 हजार 584 पुरुष, 25 लाख 13 हजार 357 महिला और 59 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

महिलाएं संचालित करेंगी 136 पोलिंग स्टेशन

इनमें 62131 सर्विस वोटर भी शामिल हैं। 2014 के आम चुनावों के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या 48 लाख 10 हजार 071 थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या 50 लाख 25 हजार 941 थी, जिसमें 25 लाख 68 हजार 761 पुरुष, 24 लाख 57 हजार 166 महिला, 14 थर्ड जेंडर मतदाता थे। मतदाता सूची में 10 अप्रैल से पहले तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की ही तर्ज पर इस बार प्रदेश के 136 मतदान केंद्रों में कुल महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करने की तैयारी की है। हर विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों को इसके लिए चुना गया है। इनमें रिटर्निंग अफसर से लेकर मतदान कर्मी भी महिलाएं ही होंगी।

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज भी होगा आपकी पहचान

चुनाव आयोग ने इस बार कई नए दस्तावेजों को फोटोयुक्त पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

हिमाचल में बदलेंगे मुआवजा देने के नियम, कैबिनेट में जाएगा मामला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार मुआवजा देने के नियमों को बदलने की तैयारी कर रही है । फोरलेन मुआवजे पर उपजे विवाद को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें किसानों को फैक्टर वन में दिए जा रहे मुआवजे पर विस्तृत चर्चा की गई। फोरलेन संघर्ष समिति वर्ष 2015 से प्रदेश सरकार पर फैक्टर टू में मुआवजा देने की गुहार लगा रही है लेकिन अभी तक किसानों को फैक्टर वन में ही मुआवजा दिया जा रहा है। फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि फोरलेन विवाद बीते 4 साल से चल रहा है लेकिन सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है।

जमीन अधिग्रहण कर हिमाचल के हजारों–लाखों प्रभावितों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के दाम में अधिगृहित कर दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में चार गुना मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन भू–अधिग्रहण के प्रभावितों को आज तक न तो चार गुणा मुआवजा मिला, न ही पुनर्स्थापना और पुनर्वास का कोई लाभ । केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक से दो फैक्टर तय करने के आदेश मुख्य है। इनमें 4 गुना तक मुआवजा देने की बात है । बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी उपस्थित रही ।

हिमाचल में 6700 पीटीए शिक्षकों का वेतन हुआ दोगुना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवारत करीब 6,800 पीटीए शिक्षकों का वेतन सरकार ने दोगुना कर दिया है। दस मार्च को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने आठ मार्च को ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी।

इन शिक्षकों को अब 144 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। एक अप्रैल 2019 से पीटीए शिक्षकों को नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में पीटीए शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का एलान किया था।

प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पीटीए पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) को 15,600 पे बैंड, 6,000 ग्रेड पे और 31,104 महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रति माह इन शिक्षकों को अब 52,704 रुपये वेतन मिलेगा।

पीजीटी, डीपीई और टीजीटी को इतना वेतन मिलेगा

पीजीटी/प्रवक्ता (स्कूल) को 10,300 पे बैंड, 4,200 ग्रेड पे, 20,880 महंगाई भत्ता मिलेगा। इन्हें प्रति माह 35,380 रुपये वेतन मिलेगा। स्कूल कैडर के डीपीई और टीजीटी को 10,300 पे बैंड, 3,600 ग्रेड पे, 20,016 महंगाई भत्ता मिलेगा।

इन शिक्षकों को प्रतिमाह 33,916 रुपये वेतन मिलेगा। सीएंडवी को 10,300 पे बैंड, 3,200 ग्रेड पे, 19,440 महंगाई भत्ता मिलेगा। इन्हें प्रतिमाह 32,940 रुपये वेतन मिलेगा। पहले इन शिक्षकों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता था। 144 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने से शिक्षकों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। अनुबंध पर नियुक्त करीब 5,500 पीटीए शिक्षकों और करीब 1,300 लेफ्ट आउट पीटीए दोनों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अगर किसी महीने में शिक्षकों की हाजिरी कम होगी तो वेतन में नियमानुसार कटौती भी होगी।

वेतन बढ़ोतरी पर पीटीए शिक्षकों ने जताया आभार

प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ (पीटीए) ने पीटीए शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तर्ज पर सभी वित्तीय और अन्य लाभ देने के लिए सरकार का आभार जताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ठाकुर, उपाध्यक्ष अमित मुखिया, वाइस चेयरमैन नरेंद्र शर्मा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य दिनेश पटियाल, राजपूत संजीव ठाकुर, रविकांत शर्मा, बलदेव राणा, देवेंद्र ठाकुर, रवि ठाकुर, कपिल वरसांटा, वीरेंद्र ठाकुर, बॉबी, अनिल शर्मा ने वेतन बढ़ाने पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताया है।

महिलाओं की विकास में अहम भूमिका: राज्यपाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महिलाओं की देश के विकास तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश तभी आगे पड़ सकता है जब महिलाओं को सम्मान मिले तथा उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। राज्यपाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि महिलाओं को वेदों में बड़ा सम्मान दिया गया है। वेदों में मिलता है कि जिस समाज में महिला का सम्मान होता है वह स्वर्ग है और जहां महिलाओं की अनदेखी की जाती है वहां नेक काम भी बेकार हो जाते है।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति में महिलाओं तथा पुरुष के बीच कोई भेद नहीं किया गया है और यह सब वेदिक काल तक जारी रहा। इस काल में महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे थी और समाज का प्रमुख अंग थी। उन्होंने कहा कि मध्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई परन्तु वर्तमान में महिलाओं को समाज में वही सम्मान दिया जा रहा और आज महिलाएं विकास के हर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज महिलाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है और विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इनकी उपस्थिति न हो।

प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाएं अधिक मेहनती और शिक्षित है और वे खेतों से लेकर बड़े–बड़े पदों पर बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने देव भूमि में नशे के खिलाफ अभियान चलाने महिलाओं की सहयोगिता की आवश्यकता पर बल दिया तथा प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को पहल को अपनाने का आग्रह किया।

हिमाचल के 324 मेधावी 14 शहरों में लेंगे मुफ्त कोचिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मेधा प्रोत्साहन योजना में देश के 14 शहरों में सूबे के 324 मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग मिलेगी। हिमाचल सरकार ने विद्यार्थियों का चयन कर लिया है । स्नातक और जमा दो कक्षा के इन 324 मेधावी विद्यार्थियों को सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एक–एक लाख रुपये की मदद करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योजना का शुभारंभ किया।

एसपीएम एंड एनआईयू के राज्य परियोजना निदेशक शक्ति भूषण ने बताया कि चंडीगढ़, ऊना, पालमपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, पंचकूला, कोटा (राजस्थान) और दिल्ली में स्थित कोचिंग संस्थानों में मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी ।

सालाना ढाई लाख आय वाले परिवारों के छात्र किए चयनित

प्रदेश भर से प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद स्नातक स्तर के 70 अभ्यर्थी, जमा दो कक्षा के विज्ञान संकाय के 200 अभ्यर्थी, कला संकाय के 31 और वाणिज्य संकाय के 23 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं।

इन विद्यार्थियों को जेईईई, नीट, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाओं, एनडीए सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक–एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मेधा प्रोत्साहन योजना में सरकार ने सालाना 2.50 लाख आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों का चयन किया है ।

अंडर ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 75 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 65 फीसदी अंक होने की पात्रता रखी गई थी । पोस्ट ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 50 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 45 फीसदी अंक होने की पात्रता थी ।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

लोकसभा चुनाव: हिमाचल में ढाई महीने नहीं होंगी नई नियुक्तियां

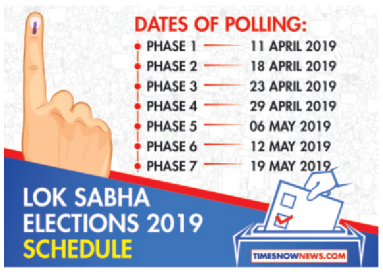

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव के एलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने से हिमाचल में ढाई महीने तक कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। 27 मई 2019 से पहले किसी भी भर्ती का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकेगा।

पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) देवेश कुमार ने बताया कि इस बारे में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सीईओ ने कहा कि अधिसूचित हो चुकी भर्तियों की प्रक्रिया जारी रह सकती है। सभी निर्माण एजेंसियों से विभिन्न निर्माण कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है ताकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर इन्हें परखा जा सके ।

सॉफ्टवेयर की मदद से 70 हजार कर्मियों में से 43,400 को चयनित कर चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। कर्मियों की तैनाती के वक्त ध्यान रखा जाएगा कि वे लोकल में तैनात न हों। उनका स्थानीय निवास या गृह विधानसभा क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए।

सवर्ण आरक्षण के लिए चार लाख आय हो सकती है शर्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालाना आठ लाख रुपये आमदनी वाले परिवारों के लिए सवर्ण आरक्षण लागू किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में भी सवर्ण आरक्षण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुके हैं और अब पात्रता के मापदंड मंत्रिमंडल की बैठक में तय होंगे ।

माना जा रहा है कि सरकार प्रदेश के सवर्ण आरक्षण के परिवारों की आय सीमा चार लाख रुपये तय कर सकती है ।

इसके अलावा आरक्षण का हकदार बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार के पास दस बीघा से अधिक जमीन न होने की शर्त लागू हो सकती है। वहीं शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को फ्लैट शर्त के दायरे में लिया जा सकता है। सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की उप–समिति गठित की थी। कमेटी ने परिवार की आय सीमा, जमीन और मकान के लिए भी मापदंड तय करने थे।

हिमाचल शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे पांच हजार नए पद, वित्त महकमे ने दी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। ऐसे में नौकरी के लिए इंतजार कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है।

हिमाचल में इस साल शिक्षकों के पांच हजार नए पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त महकमे ने मंजूरी दे दी है। नई भर्ती होने से स्कूलों में लंबे समय से खाली चल रहे पद भरे जाएंगे।

इस नई भर्ती से जयराम सरकार अस्थायी शिक्षकों की भर्तियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। नियमित शिक्षकों की भर्तियां होने से अस्थायी शिक्षकों की भर्ती बंद करने की सरकार ने योजना तैयार की है।

इसी बीच, सरकार ने एसएमसी के माध्यम से भी रिक्त पद भरने को मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती को लेकर सरकार नियम तैयार नहीं कर सकी। कोर्ट में अस्थायी शिक्षकों से जुड़े मामले विचाराधीन होने के चलते एसएमसी भर्ती को लेकर सरकार बैक फुट पर आ गई।

हिमाचल के किन्नौर में भूकंप के झटके

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में बीते दिनों भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। भूकंप की गहराई जमीन के अंदर 10 किलोमीटर रही । अभी तक भूकंप से किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हल्के झटके आते ही लोग घरों दुकानों और कार्यालयों के बाहर निकल आए।

गौरतलब है कि हिमाचल के किन्नौर में 22 फरवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र किन्नौर में जमीन के 10 किमी नीचे था। भूकंप के झटकों से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल था और लोग अपने घरों से बाहर निकल आये थे। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था।

सीएम हेल्पलाइन कार्यालय की आधारशिला रखी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को टुटीकंडी स्थित आइएसबीटी पार्किंग में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यह भवन कुछ माह में तैयार हो जाएगा। इस हेल्पलाइन के स्थापित हो जाने से प्रदेश के लोग एक क्लिक पर अपनी की शिकायतों का समाधान करवा पाएंगे। प्रदेश का कोई भी नागरिक 1100 नंबर डॉयल कर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सीएम ने कहा कि इस हेल्पलाइन को प्रभावशाली बनाया जाएगा। वह स्वयं और मंत्री इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे। इस हेल्पलाइन के माध्यम से जनमंच में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की भी निगरानी की जाएगी। यह हेल्पलाइन प्रातः सात बजे से शाम दस बज तक क्रियाशील रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से आग्रह किया कि जनहित में शुरू की जा रही इस प्रणाली को सफल बनाने में सहयोग दें। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ पंजीकृत कॉल को सिस्टम द्वारा स्वयं ही संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा।

एमसी एरिया में जल्द जनऔषधि केंद्र खोलेगा आईआईआडी
नगर निगम के साथ मिलकर सिरे चढ़ेगा प्रोजेक्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी की ओर से नगर निगम शिमला के तहत आने वाले क्षेत्र के लोगों को जनऔषधि का लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही एमसी एरिया में एक केंद्र खोला जाएगा। आईआईआरडी ने यह निर्णय नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट की ओर से दिए गए सुझाव के तहत लिया है। महापौर ने यह सुझाव जनऔषधि दिवस के मौके पर आईआईआरडी शिमला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया। कार्यक्रम में नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आईआईआरडी शनान के आसपास के गांवों के लोग और शिवालिक नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने विशेष तौर पर शिरकत की। आईआईआरडी के प्र बं ध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने मुख्यअतिथि का कार्यक्रम में स्वागत किया और संस्था की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनऔषधि दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों से की गई बातचीत का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईआईआरडी की ओर से किए जा रहे प्रयास अतुलनीय है। उन्होंने संस्था को नगर निगम की ओर से विभिन्न कार्यों में योगदान का आश्वसान देते हुए कहा कि शिमला शहर में भी जनऔषधि केंद्र खोला जाना चाहिए। उन्होंने आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा को सुझाव दिया कि वह नगर निगम के सहयोग से एमसी एरिया में भी एक जनऔषधि खोलने का प्रबंध करे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

वहीं जनऔषधि दिवस के मौके पर प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि आईआईआरडी की ओर से पूरे हिमाचल में 300 जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसी कड़ी में अब जल्द ही शिमला शहर के लोगों को लाभ देने के लिए नगर निगम एरिया में भी जनऔषधि केंद्र खोला जाएगा।

डाक्टर शर्मा ने बताया कि आईआईआरडी की ओर से जनऔषधि अभियान के विभिन्न जिलों में केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को उनके घरद्वार पर ही दवाईयां पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानि अगर कोई मरीज जनऔषधि केंद्र तक आने में असमर्थ है तो वह्टसप आदि से पर्ची मंगवाकर मिशन रीव के तहत लोगों के घरों तक दवाईयां पहुंचाई जाती है।

कार्यक्रम के आखिर में शनान में एक विशाल जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया जिसकी अगवाई खुद नगर निगम महापौर ने की। उन्होंने संस्था के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की और जनकल्याण के कार्यों में संस्था को पूरा सहयोग देने की बात भी कही।

इस मौके पर आईआईआरडी निदेशक सुषमा शर्मा, मिशन रीव लैब हैड डाक्टर केआर शांडिल, फ्लायर ग्रुप निदेशक आनन्द नायर, बीपीपीआई नोडल अधिकारी रोहित शर्मा और आईआईआरडी स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 76 वर्षीय सविता देवी की लंबी दौड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिमला रिज मैदान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित मैराथन में 700 प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई । इस मैराथन में 18 बुजुर्ग भी शामिल हुए। मैराथन की बुजुर्गों की श्रेणी में 85 साल के बीपी भाटिया और महिला श्रेणी में 76 वर्ष की सविता देवी प्रथम रहे।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

शिमला रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक तक लगेगी लिफ्ट, पर्यटकों के लिए बड़ी राहत

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

रेल मार्ग से शिमला आने वाले सैलानियों को भारी भरकम सामान उठाकर रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक तक नहीं जाना होगा। उत्तर रेलवे शिमला रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक तक आधुनिक लिफ्ट स्थापित करने जा रहा है।

बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्लेटफार्म नंबर दो के अंतिम सिरे के पास स्थित लोको शेड से विधानसभा चौक तक हाई स्पीड पावरफुल लिफ्ट बनाने की योजना है।

इसके अलावा शिमला शहर में पार्किंग की किल्लत को खत्म करने के लिए शिमला ऐक्सटेंशन (बाबा भलखू रेल संग्रहालय) के पास बहुमंजिला पार्किंग बनाने की भी योजना है।

रेलवे बोर्ड के मेंबर रोलिंग स्टॉक राजेश अग्रवाल और डिविजनल रेलवे मैनेजर अंबाला दिनेश चंद शर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीर्णोद्धार के बाद हैरिटेज लुक में तैयार किए गए रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन भवन की मुहार, वाईफाई सिस्टम, वीडियो वॉल, जीपीएस आधारित घड़ी, टच स्क्रीन क्योस्क, नए द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, कालका–शिमला रेलवे हैरिटेज सेक्शन वेबसाइट, हॉप ऑन हॉप ऑफ सेवा, एयरपोर्ट जैसी लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग, 165 किलोवाट सोलर पावर प्लांट और आधुनिक शौचालयों सहित अन्य प्रोजेक्टों का लोकार्पण भी किया।

अंग्रेजों के समय में संचार का मुख्य साधन डाक सेवा थी। रेल मेल सर्विस के माध्यम से रोजाना डाक के सैकड़ों बोरे शिमला–कालका के बीच लाए ले जाए जाते थे। बोरों को रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक तक लाने ले जाने के लिए अंग्रेजों ने यहां एक टनल बनवाई थी। रेल मेल सर्विस ऑफिस से स्टेशन प्लेटफार्म स्थित भोजनालय के पीछे तक आज भी यह टनल विद्यमान है, हालांकि अब इसका प्रयोग नहीं होता।

शिमला के कोटि गांव में लगी भीषण आग, 7 घर जलकर हुए राख, 16 परिवार प्रभावित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटि गांव में आग लगने से 7 घर जल गए। जिससे 16 परिवार प्रभावित हुए। आग लगने की घटना लगभग 1:30 बजे हुई। आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया । आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

राष्ट्रीय स्तरीय उच्च अधिकारियों ने किया निरीक्षण

सोलन मंडी की कार्यप्रणाली और आसपास के क्षेत्रों का लिया जायजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

देश भर की ई–नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से जुड़ी सब्जी और फल मंडी में से एक सोलन मंडी के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च अधिकारियों की एक टीम सोलन पहुंची। इस टीम ने मंडी की सुविधाओं सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। जानकारी के मुताबिक टीम की ओर से मंडी पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें टीम मुख्य रूप से ई–नाम से संबंधित जानकारियां हासिल कर रही है। इसमें ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों के गांव पहुंच कर उनसे भी ई–नाम को लेकर इनपुट हासिल किए जा रहे हैं। इस निरीक्षण और इनपुट में प्रथम श्रेणी में आने वाली सब्जी मंडी को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

समिति को पहले भी मिल चुका है प्रधानमंत्री पुरस्कार

राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत कारोबार करने के लिए मंडी समिति देश भर में नंबर वन है और इसके लिए प्रधानमंत्री से पहले भी पुरस्कार हासिल कर चुकी है। यहां पर हर वर्ष करोड़ों रुपयों का कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। इसके तहत किसान अपने उत्पाद यहीं से बाहर की मंडियों में ऑनलाइन बोली के तहत बेच रहे हैं। किसानों को इसके तहत उनकी अदायगी उसी दिन बैंक खाते में कर दी जाती है। यह जानकारी प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए मंडी समिति सोलन ने यह कार्यक्रम शुरू किया है।

किसानों के लिए शुरु की ई–नाम पाठशाला

कृषि उपज मंडी समिति सोलन ने किसानों को ई–नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की जानकारी देने के लिए ई–नाम पाठशाला चलाई है। इसके माध्यम से किसान ई–नाम से संबंधित जानकारियों से अवगत हो रहे हैं और पोर्टल में उनका निशुल्क पंजीकरण भी किया जा रहा है। इसके तहत कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 7460 किसानों का पंजीकरण घर द्वार पर किया जा चुका है। जिला सोलन में अब तक 16 ई–नाम पाठशालाओं का आयोजन किया गया है। इस ई–नाम पाठशला को आयोजित करने का उद्देश्य किसानों को उचित विपणन व्यवस्था उपलब्ध करवाना और शोषण मुक्त व्यापार से किसानों को अवगत करवाना है।

त्रिलोकपुर मेले में 35 सीसीटीवी कैमरों का रहेगा पहरा

रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

माहामाया श्री बालासुंदरी सिद्ध पीठ त्रिलोकपुर में 6 से 19 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र मेले मनाए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर एवं आयुक्त मंदिर न्यास ललित जैन ने चैत्र नवरात्र मेले के प्रबंधों को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने कहा कि त्रिलोकपुर में मंदिर के रास्ते पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मंदिर परिसर के भीड़ वाले क्षेत्रों में 35 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से मेले को चार सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट एवं एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 250 पुलिस एवं गृह रक्षक जवानों को विभिन्न स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। मेला क्षेत्र में लगे 35 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए मेला मजिस्ट्रेट की ओर से एक प्रशिक्षित पुलिस जवान एवं एक अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान विस्फोटक सामग्री, आग्नेय शस्त्रों को लाने और ले जाने के अतिरिक्त नारियल चढ़ाने एवं ऊंची आवाज में बैंड अथवा ढोल बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में नियंत्रण एवं सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बैठक में मेले के दौरान शौचालय की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 150 शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें से कुछ अस्थायी तौर पर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ, एलपीजी सिलिंडरों की उचित व्यवस्था करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक योजनाए जनता को समर्पित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बीते दिनों ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुटलैहड़ विधानसभा के थानाखास में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान की गई सभी घोषणाएं पूरी की है जिससे प्रदेश के विकास को नई गति व दिशा मिली है।

प्रदेश सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अभी तक 65 हजार निशुल्क गैस कुनैक्शन महिला लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आगामी तीन माह के भीतर धुआं मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुटलैहड़ विधानसभा के थानाखास में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान की गई सभी घोषणाएं पूरी की है जिससे प्रदेश के विकास को नई गति व दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आगामी तीन माह के भीतर धुआं मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बंगाणा में उप रोजगार केन्द्र तथा क्षेत्र में 15 ट्यूब वैल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 17 पंचायतों को बेहतर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 21 करोड़ रुपये की पेयजल योजना पर कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने हरोट तथा दिड़ में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमैरी को क्रियाशील करने की भी घोषणा की।

उन्होंने तीन वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा क्षेत्र की तीन अन्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने बंगाणा में दम्कल उप केन्द्र स्थापित करने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में तीन नए ट्रैड आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने अटल बिहारी बाजपयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में अंग्रेजी, हिन्दी व वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने और राजकीय उच्च पाठशाला करीयां को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा क्षेत्र की तीन प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

धारा 144 के तहत डीसी ने दिए हथियार जमा करने के आदेश

सिरमौर जिले में 8316 लोगों को जारी हुए हैं बंदूकों के लाइसेंस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने की सूरत में लाइसेंस धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ललित जैन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए जिले में सभी बंदूक, हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री को तुरंत जमा करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 23 मई को मतगणना के उपरांत एक सप्ताह तक जारी रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार जिला दंडाधिकारी की ओर से सभी बंदूक/हथियार धारकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी बंदूकें एवं विस्फोटक सामग्री को अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाएं। हथियार जमा करने पर रसीद संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से अवश्य लें। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि जिले में कुल 8316 बंदूक धारक हैं। इन्हें प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदूकें और अन्य हथियार एवं विस्फोटक सामग्री जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री और होमगार्ड पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, उन्हें प्रशासन ने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल अथवा बंदूक के लाइसेंस जारी किए गए हैं। पुलिस ऐसे लोगों का पुनः आकलन करेगी। यदि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में जान का खतरा है तो उस स्थिति में यह आदेश उन पर भी लागू नहीं होंगे।

पशु तस्करी मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

हिमाचल से पशु तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर पुलिस ने अपराधियों की धर–पकड़ की मुहिम शुरू कर दी है। हाल ही में सिरमौर पुलिस ने एक उद्घोषित अपराधी को पांच साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने भगोड़े को पंजाब के पटियाला से दबोचा है। जानकारी के अनुसार भगोड़ा अपराधी सुरेंद्र सिंह पुत्र मेहर सिंह निवासी राजपुरा, पटियाला पशु तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस ने भगोड़े को दबोचने के लिए इससे पहले भी अभियान चलाए लेकिन, सफलता नहीं मिली। इस बार पुलिस की ओर से बिछाए जाल में भगोड़ा फंस गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में 16 सितंबर को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी अदालत से भगोड़ा घोषित किया गया। मामले की पुष्टि एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि सिरमौर पुलिस के पीओ सेल ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी है।

भराड़ी में लोगों का स्वास्थ्य डेपुटेशन के सहारे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अभी भी चिकित्सकों और बुनियादी सुविधाओं की खासी कमी चल रही है। ऐसे कई चिकित्सा केंद्र हैं जहां पर लोगो को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए डेपूटेशन से जुगाड़ किया गया है। स्थानिय लोगों का कहना है कि उपममंडल घुमारवीं के तहत आने वाले भराड़ी अस्पताल में सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य राम भरोसे है। यहां स्वास्थ्य केंद्र के लिए पांच डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में मात्र एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है जबकि एक डेपुटेशन पर है लेकिन वह भी समय पर नहीं पहुंचते।

भराड़ी अस्पताल को 30 बेड से 50 बेड कर दिया गया है लेकिन डॉक्टरों की कमी से सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। भराड़ी अस्पताल में डॉक्टरों के 5 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में केवल 2 डॉक्टर ही सेवारत हैं। अस्पताल की ओपीडी रोज 250 के करीब रहती है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एके सिंह ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है।

ऊना में बनेगा पीजीआई सैटेलाईट केन्द्र, मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

बीते दिनों मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा ने ऊना जिला के मलहाट में 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पीजीआई सैटेलाईट केन्द्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला यह संस्थान आगामी लगभग 40 महीनो में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के बन जाने से प्रदेश के लोगों को उनके घरों के नज़दीक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पीजीआई सैटेलाईट केन्द्र में 300 बिस्तरों की क्षमता होगी और पीजीआई चण्डीगढ़ के बराबर विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि बिलासपुर जिला में 1352 करोड़ रुपये की लागत से एम्स का निर्माण किया जा रहा है जो आगामी दो वर्षों में बनकर पूर्ण हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि ऊना में पीजीआई केन्द्र, केन्द्र सरकार का प्रदेश के लिए एक उपहार है जो केन्द्र व प्रदेश नेतृत्व के निकट समन्वय के कारण ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि ऊना जिला विकास के क्षेत्र में राज्यों में आदर्श जिला के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआं है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुलाचर में 1.08 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उप–तहसील भवन और 6.78 करोड़ रुपये की लागत से होने वाली अमराली –बीतन–बिनेवाल सड़क के उन्नयन कार्य की आधारशिलाएं रखीं। मुख्यमंत्री ने 1.53 लाख रुपये की लागत से निर्मित बथारी पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने 3.62 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत होने वाले लालड़ी –कुंगरात –धिलवां सड़क तथा 10 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत होने वाले मनाल – बल्लीवाल –पुबोवाल–लालुवाल–पुलियां सड़क की भी आधारशिला रखी। उन्होंने बढेरा में छात्रावास की आधारशिला तथा 'हिमकेप्स' की 7.50 करोड़ रुपये की लागत से बनी सौर सयंत्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने आईआईटी सलोह में 2.76 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की आधारशिला तथा 13 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत होने वाली ऊना संतोखगढ़ सड़क की भी आधारशिला रखी।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, संगठन सचिव पवन राणा, विधायक बलवीर चौधरी, राजेश ठाकुर, अरुण मेहरा, हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीन शर्मा, एसआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार, बलवीर बग्गा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। के शिलान्यास व लोकार्पण किए।

बिलासपुर में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिकल बसें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर में जल्द ही लोग इलेक्ट्रिकल बसों में सफर कर सके हैं। इसके लिए एचआरटी जिला प्रबंधन की ओर से कवायद शुरू हो चुकी है।

पहले चरण में केवल पांच बसें ही चलाई जाएंगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो और बसें भी चलाई जा सकती हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रिकल बसों के बिलासपुर आने से पहले इसके लिए चार्जिंग की व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एचआरटीसी बिलासपुर में तीन चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं। जहां इलेक्ट्रिकल बसों को चार्ज किया जाएगा। इसके लिए बिजली बोर्ड की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। वहीं करीब साढ़े नौ लाख की राशि भी बिजली बोर्ड को जारी कर दी गई है। राशि मिलने के बाद बिजली बोर्ड जल्द ही बसों के लिए चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए बिजली की व्यवस्था कर देगा। एचआरटीसी की योजना है कि मनाली में चलने वाली इलेक्ट्रिकल बसों को सर्दी के मौसम में मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर आदि स्टेशनों पर चलाया जाएगा। उसके लिए भी इन जिलों में चार्जिंग प्वाइंट होना जरूरी है। बिलासपुर जिला को पांच नई इलेक्ट्रिकल बसें मिलेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए बनाए थे अलग उम्र के आधारकार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

झंडूता के बेहरन में फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र बनवाते पकड़े युवक ने पुलिस के समक्ष कई राज उगले हैं। आरोपी शिशुपाल (22) गांव नगलामहू जिला अलीगढ़ पर क्रिकेट खेलने का इतना खुमार है कि उसने अलग–अलग उम्र के कई आधार कार्ड बनाए हुए हैं। उसने 16, 19, 20, साल की उम्र के जाली आधार कार्ड बनाए हुए थे ताकि वह हर उम्र की टीम का हिस्सा बनकर क्रिकेट मैच खेल सके। पुलिस को उसके पास से एक मतदान पहचान पत्र भी बरामद हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का है। इस पर भी उसका नाम पता व जन्मतिथि अलग है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि हिमाचल की अंडर–19 क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए उत्तरप्रदेश का एक युवक हिमाचली प्रमाण पत्र बनवाते पकड़ा गया था। उसने बिलासपुर के स्थायी निवासी अपने दोस्त सेर गांव के सौरव का आधार कार्ड चुराकर उस पर अपना फोटो चिपका दिया। वह हिमाचल का प्रमाण पत्र बनवाने बेहरन पटवारघर पहुंचा, तो उसकी चालाकी पटवारी ने पकड़ ली। शिशुपाल और उसका दोस्त सौरव चंडीगढ़ में निजी अकादमी में क्रिकेट की कोचिंग ले रहे थे।

यहीं पर उसने हिमाचल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए धोखाधड़ी की। डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा का कहना है कि युवक के पास से अलग–अलग उम्र के दो से तीन आधार कार्ड मिले हैं जिन पर जन्मतिथि अलग–अलग है।

2007 में हुआ था ऐसा फर्जीवाड़ा

क्रिकेट मैच को लेकर 2007 में ही ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा हुआ था जिसमें अधिकारियों सहित तहसीलदार फंसे थे। शिमला विजिलेंस की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। इसमें भी कई युवाओं के फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र बनाकर हिमाचल की टीम से खिलाया गया था।

सरस मेला 17 से 27 मार्च तक लगेगा

बिलासपुर

नलवाड़ी मेले के साथ–साथ जिला के लोग सरस मेले का भी लुत्फ उठा सकेंगे। बिलासपुर 17 से 27 मार्च तक सरस मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों के स्वयं सहायता समूह हाथों से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। बिलासपुर में इससे पहले कभी भी सरस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। केवल मंडी, कुल्लू, सहित चंबा में सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर हर साल लोग विभिन्न राज्यों में हाथों से बने उत्पादों व व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में बिलासपुर में भी काफी समय से लोगों की मांग थी कि यहां पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाए। हालांकि पहले यहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार जिला प्रशासन के प्रयासों से सरस मेला करवाने को लेकर भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई। इसके बाद प्रशासन ने सरस मेले को लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। सभी जिलों के उपायुक्तों सहित देश के सभी राज्यों के विभागीय सचिवों को न्योता भेजा गया है कि वह सरस मेले के लिए अपने स्वयं सहायता समूहों को भेजें।

पीओ डीआरडीए संजीत सिंह ने बताया कि सरस मेले में स्वयं सहायता समूहों को बुलावा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों सहित राज्यों से विभागीय सचिवों को न्योता भेजा गया है। इस बार बिलासपुर में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा।

मेले में करवाए जाते हैं निःशुल्क स्टाल मुहैया

सरस मेले में आने वाले स्वयं सहायता समूहों को निःशुल्क स्टाल मुहैया करवाए जाते हैं, इसके अलावा उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाती है। पूरा का पूरा खर्चा प्रशासन की ओर से किया जाता है ताकि बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि भारत सरकार की ओर से सरस मेले के आयोजन को लेकर अलग से सहायता मुहैया करवाई जाती है।

सरस मेला

सरस मेले में विभिन्न जिलों, राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने हाथों से बने हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं। इस मेले के जरिये वह अपने राज्य व जिला की प्रसिद्ध उत्पाद सहित व्यंजनों को प्रस्तुत करते हैं। लोग इन उत्पादों व व्यंजनों की खरीदारी भी कर सकते हैं। सरस मेले के जरिये लोग एक ही जगह पर देश के अलग–अलग राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों व व्यंजनों के बारे में जान सकते हैं। बिलासपुर में पहली बार सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है।

खैरी में बनेगा गोसदन, मंत्री ने किया शिलान्यास

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री विरेंद्र कंवर ने बीते दिनों सुजानपुर विस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने ग्राम पंचायत बैरी में लगभग साढ़े चार लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित पंचायत घर भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत खैरी के जंगलबैरी में दो करोड़ 56 लाख की लागत से 153 कनाल भूमि पर निर्मित होने वाले गोसदन और ग्राम पंचायत जंदरू में 8 लाख 50 हजार की लागत से बनने वाले पंचायत घर के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत खैरी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गोवंश संवर्धन के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। भूमि की उपलब्धता अनुसार गो अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं।

जंगलबैरी में बनने वाले गोसदन में 400 पशुओं के पालन की व्यवस्था की जाएगी। यहां तूड़ी के लिए शेड निर्मित किए जाएंगे और केंचुआ खाद बनाने तथा बायोगैस उत्पादन की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग साढ़े सात लाख किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है। सरकार ने दूध खरीद मूल्य में भी दो रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मत्स्य क्षेत्र में भी ट्राउट मछली उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 550 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में बेहतर कार्य करने पर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला मंडल री भलाणा, जोल, तनेकड़, चौकी, दरसाल, टिहरा, बैरी, पटलांदर, राजनगर, मरहाना, मंढेतर और भारथु को सम्मानित किया। वहीं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 98 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। ग्राम पंचायत खैरी में पंचायत घर के निर्माण को 20 लाख तथा पंचायत घर बैरी में टाइलें लगाने और शेड के निर्माण के लिए पांच लाख की अतिरिक्त राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। जंदरू पंचायत घर का निर्माण 25 लाख रुपये से किया जाएगा।

झंडूता में 40 हजार लोगों के लिए दो डॉक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

उपमंडल झंडूता में करीब 40 हजार से अधिक लोगों का स्वास्थ्य दो डॉक्टरों के सहारे है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का कारण करना पड़ रहा है। कई बार डॉक्टर के अवकाश पर होने या फिर कोर्ट एविडेंस के कारण यहां परेशानी और भी बढ़ जाती है। कई बार आपातकाल में तो घायलों का उपचार करना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि लोगों ने इस बारे कई बार सरकार से रिक्त पद भरने की मांग की लेकिन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत ऐसी बनी है कि एक डॉक्टर के हवाले 20 हजार लोगों का स्वास्थ्य टीका हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता में डाक्टरों के पांच पद सरकार की ओर से स्वीकृत है लेकिन मौजूदा समय में मात्र दो डॉक्टरों को ही हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच करनी पड़ती है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु उपमंडल स्तर का अस्पताल होने के कारण आए दिन क्षेत्र में कई दुर्घटनाओं के कारण लोग झंडूता अस्पताल में ही आते हैं। ऐसे में यहां डॉक्टरों के पद खाली होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

झंडूता अस्पताल से करीब 40 हजार से अधिक की आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है लेकिन डॉक्टर न होने के कारण यहां कई बार लोगों को बगैर उपचार के ही घर लौटना पड़ता है।

तिब्बत विद्रोह दिवस पर बौद्ध भिक्षु की संदिग्ध मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

तिब्बतियों के 60वें विद्रोह दिवस (अपराइजिंग डे) पर सिद्धबाड़ी में एक बौद्ध भिक्षु का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी मच गई। बौद्ध भिक्षु के हाथ की नसें भी कटी पाई गईं, जिनसे खून बह रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बीते 10 मार्च को को एक ग्रामीण ने तपोवन विधानसभा परिसर के समीप सिद्धबाड़ी में सिद्ध बाबा गोरिया मंदिर के साथ लगते बाग की झाड़ियों में शव को पेड़ से लटके हुए देखा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में ले लिया।

बौद्ध भिक्षु के पास एक आधार कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेज मिले हैं। आधार कार्ड के अनुसार बौद्ध भिक्षु की पहचान सोनम तोपदेन (38) पुत्र छेरिंग रिनछेन निवासी दोनीलिंग मानिस्ट्री सहस्त्रधारा रोड, डिक्यलिंग तिब्बतियन बस्ती किरसाली कुल्हन मानसिंह देहरादून (उत्तराखंड) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बौद्ध भिक्षु जंगल में ध्यान लगाता था। उसके साथियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि सोनम का मन ध्यान में नहीं लगता था। इससे पहले भी वह तीन–चार मठ बदल चुका था और लंबे समय से मानसिक तनाव से ग्रस्त था। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का पता किया जा रहा है।

9 तोले सोना व 15 तोले चांदी सहित 25 हजार ले उड़े चोर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

जिला कांगड़ा में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में पंचायत सुगनाड़ा में एक घर के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपये के गहने और नकदी उड़ा ले गए। जिस दौरान चोरी हुई, उस समय परिवार के सदस्य हमीरपुर स्थित दियोटसिद्ध माथा टेकने गए हुए थे। इससे साफ है कि आरोपी पहले पूरी रेकी कर वारदात को अंजाम दे रहा हैं। बहरहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार सुगनाड़ा निवासी दिनेश कुमार पुत्र बुद्धि सिंह 8 मार्च को दियोटसिद्ध में बाबा बालक नाथ मंदिर गए। 9 मार्च सुबह जब दिनेश का बड़ा भाई जगपाल सिंह उठा तो मकान का मुख्य द्वार खुला था। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। इसकी सूचना फोन पर दिनेश को देने के बाद पुलिस चौकी नगरोटा सूरियां को भी सूचित कर दिया। शनिवार शाम 4 बजे के करीब दिनेश कुमार अपने परिवार के साथ वापस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके घर से चोरों ने करीब 6 कमरों के ताले तोड़े हुए थे। कमरे के अंदर रखा सारा सामान इधर–उधर फेंका हुआ था। वहीं घर के अंदर रखी अलमारी खोली हुई थी। उन्होंने बताया कि चोर करीब 9 तोले सोना, 15 तोले चांदी और करीब 25 हजार की नकदी पर हाथ साफ कर गए हैं।

तकनीकी विवि और नादौन अस्पताल का उद्घाटन रुका

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

चुनावी आचार संहिता 10 मार्च से लागू होने के कारण जिला के कई विकास कार्य रुक गए हैं। आचार संहिता के कारण लोगों को इन कार्यों का लाभ अब चुनावों के बाद ही मिल पाएगा। इन कार्यों में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन, नादौन अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन, लोक निर्माण भोरंज के नए सब डिविजन कार्यालय का उद्घाटन, भोरंज अस्पताल का निर्माण कार्य, सुजानपुर के जंगलबैरी में गो सेंचुरी का निर्माण आदि शामिल हैं।

प्रदेश में 19 मई को चुनाव हैं। अब आचार संहिता समाप्त होने और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद ही विभिन्न विकास कार्य शुरू हो पाएंगे। जिले में नादौन अस्पताल का उद्घाटन होने की लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें अब इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग सब डिविजन भोरंज के कार्यालय का उद्घाटन 11 मार्च को रखा गया था लेकिन, 10 मार्च को चुनावी आचार संहिता के कारण यह भी रुक गया।

पॉलीथिन के प्रयोग पर छह दुकानदारों से वसूले 34 हजार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीते दिनों पॉलिथीन का प्रयोग करने पर गलोड़ क्षेत्र के छह दुकानदारों के चालान कर 34 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। विभाग के बड़सर क्षेत्र के निरीक्षक विनोद कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान विभागीय टीम ने दुकानदारों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने की भी हिदायत दी है। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में भी खलबली मच गई।

प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई दुकानदार इसका प्रयोग कर रहे हैं। गलोड़ क्षेत्र में छापे के दौरान विभाग की टीम ने ऐसे छह दुकानदारों को पकड़ा है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पॉलिथीन के खिलाफ विभागीय टीमें निरंतर निरीक्षण करेंगी। अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गलोड़ क्षेत्र में छह दुकानदारों के चालान किए गए हैं। दुकानदारों से 34 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है।

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।
द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334, Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

प्रशासन की दो टूक, बिना लाइसेंस न करे पैराग्लाइडिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

पर्यटन स्थल खज्जियार में पुलिस ने बिना लाइसेंस के चार पैराग्लाइडरों को पकड़ा है। साथ ही लोगों को बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने बिना लाइसेंस हो रही पैराग्लाइडिंग की रिपोर्ट तैयार की है। खज्जियार में बिना लाइसेंस हो रही पैराग्लाइडिंग की वजह से अब तक तीन पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन हादसा होने के बाद कुछ समय के लिए खज्जियार में पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा देता है जबकि, मामला शांत होने के बाद दोबारा से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाती है। हालांकि, पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक चंबा में किसी को भी पैराग्लाइडिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है।

पुलिस को पिछले कुछ दिनों से खज्जियार में बिना लाइसेंस के हो रही पैराग्लाइडिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने खज्जियार में दबिश दी। इस दौरान उन्होंने चार पैराग्लाइडर बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग करते हुए पकड़े। पुलिस ने स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए समझाया कि बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग करना गैर कानूनी है। इससे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा न दें। पर्यटकों को भी इस तरह के जोखिम से बचने की सलाह दी गई।

चुराह के खुशनगरी और चुहाड़ में दो माह से जलसंकट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

चुराह के खुशनगरी और चुहाड़ गांव में पानी का संकट गहरा गया है। दो महीने से दोनों गांवों की पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है। ग्रामीणों को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। दो माह पहले पेयजल सप्लाई के मुख्य स्रोत खब्बू नाला में भूस्खलन होने से पेयजल पाइप क्षतिग्रस्त हो गई थी जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। इससे उपरोक्त गांव में पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। ग्रामीणों को दूसरे गांव जाकर पीने का पानी ढोना पड़ रहा है। आईपीएच विभाग को बार-बार समस्या से अवगत करवाने पर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन और विभाग से जल्द पेयजल सप्लाई बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांवों में करीब 70 परिवार रहते हैं जो दो महीने से पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। गर्मियां शुरू होने वाली हैं। अगर विभाग ने समय रहते पेयजल सप्लाई की टूटी पाइपों को दुरुस्त नहीं करवाया तो ग्रामीणों को गर्मी में पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि पेयजल सप्लाई जल्द बहाल करवाई जाए। उधर विभागाधिकारियों का कहना है कि इस बारे में जल्द कार्रवाई की जाएगी।

धर्मपुर में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

विस क्षेत्र धर्मपुर में एक उपलब्धि और जुड़ गई है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मपुर में केवी खोलने को मुहर लग गई है। इस विद्यालय के खुलने से क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, संधोल के बाद अब धर्मपुर में भी केंद्रीय विद्यालय होगा। गौरतलब है कि लोगों की मांग पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने धर्मपुर में केवी खोलने के प्रयासों को गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर के समक्ष लोगों की मांग रखी, जिसे मंजूरी मिलने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आईपीएच मंत्री ने कहा कि वीरवार को केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसको विधिवत रूप से स्वीकृति मिल गई है। जल्द यहां केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

चुराह के सेईकोठी पंचायत के चार गांवों में दो माह बाद भी अंधेरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो , चंबा

चुराह उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सेईकोठी के चार गांवों पिछले दो महीने से अंधेरे में है। इस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारे वह कई बार विद्युत बोर्ड से गुहार लगा चुके हैं। मगर अभी तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं, विद्युत बोर्ड की मानें तो बर्फबारी के कारण पंचायत में बिजली तारों को काफी नुकसान हुआ है। खंभे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिजली बोर्ड के कर्मी भी बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। मगर अभी तक सेईकोठी रोशन नहीं हो पाया है।

जानकारी के अनुसार पंचायत के गांव हाईलरा, कंडरोलू और बरकयिढूं चैयूली में करीब बीस परिवार गुजर बसर करते हैं। बिजली गुल होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बर्फबारी से बिजली लाईनें क्षतिग्रस्त हो गई है। अन्य इलाकों को बोर्ड रोशन कर रहा है। लेकिन, अभी तक उनके गांवों में आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। लोगों ने विद्युत बोर्ड से गुहार लगाई है कि जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। विद्युत बोर्ड तीसा अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

सुधराणी-थाटा सड़क नहीं हुई बहाल, बढ़ी परेशानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

सराज विधानसभा क्षेत्र में बर्फबारी और भू स्खलन से अभी तक अधिकांश संपर्क मार्ग बहाल नहीं हो पाए हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत तुंग जहलगाड़ के पूर्व प्रधान भीखम राम ने बताया कि पिछले दो माह से क्षेत्र की दुर्गम पंचायत थाटा और बूंग जहल गाड़ को उपमंडल सराज और जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एक मात्र सड़क सुधराणी-थाटा अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। ऐसे में क्षेत्र के कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और आम लोगों को 6-7 किलोमीटर पैदल चल कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इन सड़क की बहाल के लोनिवि को आदेश दिए थे। इस सड़क को बालीचौकी से थाटा-गाड़ा गुशैणी तक डीएमआर जिले की मुख्य सड़क घोषित की गई है लेकिन, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते और मौसम साफ होने पर आज तक इस सड़क को बहाल नहीं किया गया है। सड़क बहाल न होने से लोगों को मजबूरी में छोटे वाहनों से भारी भरकम राशि अदा करने पर अपने गंतव्यों तक पहुंचना पड़ रहा है। क्षेत्र के महेंद्र सिंह, संत राम, केशव राम, केहर सिंह, हेम राज सहित अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए शीघ्र सड़क को बहाल करवाया जाए।

कासन दुग्ध अभिशीतन केंद्र में 7000 लीटर दूध हो सकेगा स्टोर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कासन में 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित दुग्ध अभिशीतन केंद्र (चिलिंग प्लांट) तथा 13.80 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन सडोह की दूसरी मंजिल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तुंगल क्षेत्र में किसान दुधारु पशु पालते हैं। इस कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए कासन में दुग्ध अभिशीतन केंद्र का निर्माण किया गया है। इसमें पूरे तुंगल क्षेत्र का दूध एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र को बनाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 7000 लीटर तक दूध स्टोर करने की क्षमता है। इसलिए कोटली के पुरानी तकनीक वाले दुग्ध अभिशीतन केंद्र को भी कासन के लिए स्थानांतरित किया जाएगा ताकि किसानों से प्राप्त दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने लुसाई खड्ड से पधर तक कंकरीट बिछाने के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर राज्य दुग्ध परिसंघ के अध्यक्ष निहाल चंद, प्रबंधक राकेश पाठक, सहायक प्रबंधक डीपी शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण प्रदीप ठाकुर, सहायक अभियंता धर्मेंद्र वर्मा, खंड विकास अधिकारी शैफाली शर्मा, अधिशासी अभियंता आईपीएच अरुण शर्मा, अधिशासी अभियंता ग्रामीण विकास राजेश शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत कासन सीता राम ठाकुर, उपप्रधान कमल किशोर, प्रधान ग्राम पंचायत सडोह कमलेश कुमार, कोटली पंचायत प्रधान निर्मला देवी, साई पंचायत प्रधान अच्छरी देवी, प्रभारी दुग्ध केंद्र कासन शशिपाल शर्मा, फील्ड अधिकारी हेमराज कालिया, चंद्रशेखर, मनोज कुमार, अनंतराम, मुरारी लाल, सुदर सिंह, पूर्व प्रधान हेम सिंह और ओम प्रकाश मौजूद रहे।

साढ़े पांच करोड़ से बनेगी छानीआगे-सीस सड़क

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

गड़सा घाटी के गांव ठेला में 5 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाली छानीआगे-सीस सड़क का वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि करीब पौने आठ किलोमीटर लंबी इस सड़क का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा तथा इससे घाटी के दुर्गम गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।

घाटी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहां एक नेचर पार्क विकसित किया जाएगा तथा घाटी में पैराग्लाइडिंग व अन्य साहसिक खेल गतिविधियों की संभावना तलाशी जाएगी। वन मंत्री ने कोठी के रास्ते व सामुदायिक भवन के लिए दो लाख रुपये, महिला मंडल रोगणा को 25 हजार, महिला मंडल भवन खारका को एक लाख, जेष्ठा के श्मशान घाट के लिए मनरेगा के तहत दस लाख और ठेला स्कूल की चारदीवारी एवं खेल मैदान के लिए भी राशि का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पारली पंचायत में विद्युत संचालित स्पैन लगाया जाएगा और जेष्ठा में नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। जेष्ठा की एक अन्य सड़क की फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने ऋषि युवक मंडल के लिए खेलों का सामान उपलब्ध करवाने तथा भुंतर भलाण बस के रूट को बढ़ाने की घोषणा भी की। मंत्री ने 136 महिलाओं को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन भी वितरित किए। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक कुल्लू जिला की करीब 6400 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से भी जिला की 8000 महिलाओं को रसोई गैस प्रदान की जा चुकी है।

स्लम एरिया में जगाई शिक्षा की लौ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू के गांव चिपणी, डाकघर बठाहड़, तहसील बंजार में लग्न चंद और देवकु देवी के घर जन्मी धनेश्वरी (21) समाजसेवा कर रही है। धनेश्वरी ने कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ-साथ कुछ अलग करने की सोची। धनेश्वरी ने जिला मुख्यालय से तीन किलोमीटर दूर रामशिला के पास लुगड़भट्टी में स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उस समय वह अकेली थी। अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों की रोज कक्षाएं लेना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने कोई शुल्क भी नहीं लिया। तब से लेकर आज तक वह रोजाना चार से छह बजे तक स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा रही है। शुरूआत में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के लिए यह सब करना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। स्नातक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही धनेश्वरी कहती है कि वह जब भी इन बच्चों को देखती थी तो लगता था कि इन बच्चों को भी शिक्षा का हक है। उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने इस मुहिम को समर्पण का नाम दिया। स्लम एरिया के बच्चों की रोजाना दो घंटे क्लास के अलावा रविवार को अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। आज वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कार सेवा दल कुल्लू इस सराहनीय कार्य के लिए धनेश्वरी को सम्मानित कर चुका है। धनेश्वरी हर रविवार को बच्चों से अतिरिक्त गतिविधियां करवाती है। रविवार को होने वाली गतिविधियों में बच्चों को कविताएं पढ़कर सुनाना, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता शामिल होती हैं। इसी वर्ष सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले नरेश ने राज्य स्तरीय जूनियर फुटबाल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जबकि अन्य बच्चे भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। धनेश्वरी की स्पेशल क्लास में बच्चे रोजाना अपना स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं। बच्चों को धनेश्वरी से अधिक लगाव है। बच्चे धनेश्वरी को अपनी अध्यापिका समझते हैं। धनेश्वरी भी बच्चों को बहुत प्यार करती है।

चुनाव में रोहतांग सुरंग से कर सकेंगे आवाजाही

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

रक्षा मंत्रालय ने निर्माणाधीन रोहतांग टनल से आम लोगों की आवाजाही को हरी झंडी दे दी है। अब नॉर्थ पोर्टल तक सड़क बहाल होते ही टनल होकर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दशकों बाद घाटी में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के कारण इस बार रोहतांग दर्रा के देर से खुलने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत न आए, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने रोहतांग टनल होकर आवाजाही को अपनी मंजूरी दे दी है।

कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा के आग्रह पर रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने आवाजाही को मंजूरी दी है। मारकंडा ने रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष लाहौल-स्पीति की वस्तुस्थिति रखी। लोकसभा चुनाव और बर्फबारी के बीच फंसे लोगों की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रालय ने दर्रा बहाल

होने तक टनल से लोगों की आवाजाही को मंजूरी प्रदान की है। रोहतांग दर्रा बहाल होने के बाद टनल होकर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। कृषि मंत्री मारकंडा ने कहा कि इससे पहले मनाली-सरचू मार्ग को रोहतांग टनल के नार्थ पोर्टल तक जल्द खोलने के रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। बताया कि राज्य सरकार ने हालांकि लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए पवन हंस के साथ सेना के दो हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। लेकिन खराब मौसम के कारण बीच में नियमित उड़ानें नहीं हो पाई। कहा कि अभी भी सैकड़ों लोगों को रोहतांग के आरपार करवाया जाना है। टनल से आवाजाही शुरू होने से हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं रहेगी।

चौहटा की जातर में बड़ादेव कमरुनाग से मिलकर विदा हुए देवता

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

बाबा भूतनाथ के प्रांगण चौहाटा बाजार में 11 मार्च की सुबह का नजारा देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों धरती पर स्वर्गलोक उतर आया हो। सोने चांदी और मखमली कपड़ों से सजे देवरथ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे क्योंकि अब यह नजारा एक वर्ष बाद देखने को मिलेगा। देवदर्शन के साथ लोग विदाई लेते देवी-देवताओं के भावुक क्षणों के गवाह भी बने। विदाई के इन पलों में देव और मानस की रिश्तों की पराकाष्ठा भी चरम पर नजर आई। चौहटा की जातर के बाद अंतरराष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि में भाग लेने आए करीब 200 देवी देवता अपने देवालओं को वापस लौट गए हैं। देवी-देवताओं के आने से सात दिन से छोटी काशी देवमयी बनी हुई थी। मगर देवताओं के जाने से मंडी नगर में एक उदासी का सा माहौल छा गया। मंडी शिवरात्रि में आए देवता अपने परिजनों की तरह एक दूसरे से मिलकर एक साल के लिए जुदा हुए। अगली साल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ जनपद के देवी-देवता अपने-अपने धाम लौट गए।

टारना से उतरे बड़ादेव कमरुनाग

मंडी जनपद के बड़ादेव कमरूनाग भी टारना मंदिर का अपना आसन छोड़ कर देवी देवताओं को विदा करने के लिए चौहटा की जातर में आए। बड़ादेव ने कुछ देर के लिए सेरी चानणी की पौड़ियों में अपना आसन जमाया तो उनके दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ादेओ से मिलकर देवता वापस अपने अपने गांव के गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

परिवार में बच्चों के भी हैं कानूनी अधिकार

भारत में जहां तक बच्चों के अधिकार का सवाल है तो बच्चे मारपीट या किसी भी तरह की प्रताड़ना से कानून में पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। राइट–टू–एजुकेशन ऐक्ट के तहत टीचर भी बच्चे को डरा–धमका और पीट नहीं सकते । ऐसा करने पर केस दर्ज होगा और उनकी नौकरी भी जा सकती है ।

बच्चों द्वारा अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज कराने के मामले भारत में हालांकि काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में यह अक्सर होता है ।

क्या कहता है जेजे ऐक्ट

अगर बच्चे को पैरंट्स टार्चर करते हैं या पीटते हैं तो जेजे (जूवनाइल जस्टिस) ऐक्ट में पुलिस से शिकायत की जा सकती है। यदि बच्चे को चोट पहुंची है तो फिर आईपीसी के तहत केस दर्ज होगा। आईपीसी हो या जेजे ऐक्ट कानून में कही भी पेरेंट्स अपवाद नहीं हैं। जेजे ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा ही सकती है। यह मामला जमानती है।

नप सकते हैं IPC में

मारपीट पर आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज होगा, जो गैर–संज्ञेय है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। बच्चे को कोर्ट में खुद ही अपना केस लड़ना होगा और जुर्म साबित होने पर जुर्माना या एक साल की कैद हो सकती है। लेकिन नुकीले हथियार से मारने पर धारा 324 लगती है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जानलेवा चोट पहुंचाने पर 326 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें 10 साल तक या उम्रकैद तक सजा का प्रावधान है। सिर पर चोट लगने पर 308 (गैर–इरादतन हत्या का प्रयास) का केस बनेगा। इसके तहत 3 से 7 साल तक कैद हो सकती है। 326 और 308 दोनों गैर–जमानती हैं। अन्य धाराओं के तहत अलग–अलग सजा का प्रावधान है।

मुकदमा होने पर क्या करें

केस दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत लेनी होगी। मामला समझौतावादी होने पर पिता–बच्चे की इच्छा से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन गंभीर धाराओं (326 और 308) में एफआईआर दर्ज होने पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। गैर–समझौतावादी मामले में सिर्फ हाई कोर्ट से ही एफआईआर रद्द हो सकती है। हालांकि कोर्ट में बच्चे को पीटने के पीछे का मोटिव भी देखा जाता है। यदि गलत हरकत से रोकने के लिए या ना पढ़ने पर पीटा गया हो तो बचाव पक्ष इसकी दलील देकर सजा में राहत हासिल कर सकता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

पेल्विक कन्जेशन सिंड्रोम: हर तीसरी महिला है इस बीमारी की शिकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :अधिकतर महिलाएं अपने जीवन के किसी न किसी स्तर पर पेट के निचले हिस्से के दर्द से परेशान रहती हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड्स के दौरान या लंबे समय तक बैठे रहने से यह समस्या बढ़ जाती है। अगर पेट दर्द की समस्या छह महीने से अधिक समय तक रहती है, तो यह पेल्विक कन्जेशन सिंड्रोम (PCS) के कारण हो सकता है। दुनियाभर की हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन के किसी ना किसी स्तर पर इस दर्द से पीड़ित होती हैं।

क्या है पेल्विक कन्जेशन सिंड्रोम

पेट के निचले भाग में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे सामान्य कारणों में से एक है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम यानी PCS यह बीमारी आमतौर पर युवतियों में होती है। पेल्विक कन्जेशन सिंड्रोम को पेल्विक वेन इनकॉम्पिटेंस या पेल्विक वेन इनसफिशंसी भी कहते हैं। यह महिलाओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट में तेज दर्द होता है, जो खड़े होने पर और बढ़ जाता है। हालांकि लेटने पर थोड़ा आराम मिलता है। PCS जांघ, नितंब या योनि क्षेत्र की वैरिकोज वेन्स से संबंधित होता है। इसमें शिराएं सामान्य से अधिक खिंच जाती हैं।

बीमारी के कारण

वैसे तो इस बीमारी का ठोस कारण अब तक मेडिकल साईंस में सामने नहीं आया है। लेकिन, बॉडी स्ट्रक्चर या हार्मोन्स के स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी को डॉक्टर PCS का बड़ा कारण मानते हैं। इससे प्रभावित होने वाली ज्यादातर महिलाएं 20 से 45 आयु वर्ग की होती हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन संबंधी बदलावों, वजन बढ़ने और पेल्विक क्षेत्र की अनैटमी में परिवर्तन आने से अंडाशय की शिराओं में दबाव बढ़ जाता है जिससे शिराओं की दीवार कमजोर हो जाती है। फिर वो सामान्य से अधिक फैल जाती हैं। जब अंडाशय की शिराएं फैल जाती हैं, तो वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं होता है जिससे रक्त वापस बहकर शिराओं में आ जाता है। इसे रीफ्लेक्स कहते हैं। इसके चलते पेल्विस एरिया में ब्लड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। PCS बेली बटन के नीचे और दोनों नितंबों के बीच होता है और छह महीने से अधिक समय तक रहता है।

ये हैं लक्षण

डॉक्टरों के मुताबिक, इसका सबसे प्रमुख लक्षण पेट के निचले भाग में दर्द होना है। यह अधिक देर तक बैठने या खड़े रहने के कारण गंभीर हो जाता है। इसके कारण कई महिलाओं को पैर में भारीपन भी लगता है। इसके अलावा पेल्विक एरिया में लगातार दर्द होना, पेट के निचले भाग में मरोड़ अनुभव होना, पेल्विक एरिया में दबाव या भारीपन अनुभव होना, शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना, यूरीन या मल त्यागते समय दर्द होना आदि शामिल हैं।

उपचार

डॉक्टरों के मुताबिक यह एक नॉन–सर्जिकल प्रक्रिया है। इसके बाद थोड़ा दर्द होता है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। यह PCS का एक मिनिमली इनवेसिव ट्रीटमेंट है जिसमें जिन शिराओं में खराबी आ जाती है उन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि उनमें रक्त जमा न हो। एम्बलाइजेशन ब्लीडिंग को रोकने में बहुत प्रभावी है और ओपन सर्जरी की तुलना में बहुत आसान है। इसमें अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होती ।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

जाने खुद को Positive कैसे रखे

1) अपने दृष्टिकोण (नजरिये) में सुधार लाये :

एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, सबसे प्रभावशाली तरीको में से एक है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा सोचना कैसा है सकारात्मक या नकारात्मक क्योकि हम जैसा सोचते है वैसे बनते है।

हर चीज के दो पहलू होते है, अच्छा और बुरा, सकारात्मक लोग दोनों ही पहलू या परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक ही रखते है। वही नकारात्मक लोग हर चीज में बुराई और नेगेटिविटी ही देखते एवं खोजते है।

2. अपने आस–पास का माहौल सकारात्मक बनाये :

आप अपना समय बिताने के लिए क्या विकल्प चुनते है, जैसे : टीवी देखना , इंटरनेट , मैगज़ीन आदि । यह भी आपके विचार पर निर्भर करता है। जैसे आप टीवी में क्या देखना पसंद करते है.. क्या पढ़ना पसंद करते है ? सकारात्मक या नकारात्मक, ध्यान से विचार करें आप अपने दिमाग में क्या सोचते है ?

3. कृतज्ञ बने :

कृतज्ञ का अर्थ है , आभारी होना , शुक्रगुजार होना, जो लोग कृतज्ञ की भावना को प्रकट करते है। वे अधिक सकारात्मक और खुश रहते है। छोटी–छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ बने। जैसे भगवान ने आपको ये जीवन दिया , परिवार , मित्र , घर और भी बहुत कुछ, आप अगर अपने समिप में अच्छी चीजो की सूचि बनायेगे तो पाएंगे की अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें है। अगर आपके पास आँखे है , आप चल फिर सकते है.... तो आप ईश्वर को इसके लिए भी धन्यवाद करे।

4. अच्छी नींद लें :

आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गयी है। ना तो समय पर सो पाते है, ना ही पर्याप्त नींद ले पाते हैं, इस अपर्याप्त नींद से तरह–तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। नींद ना पूरी होने पर चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, हमें जल्दी गुस्सा आता है, स्ट्रैस रहता है , तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे में तो हम सकारात्मक नहीं रह सकते है।

5. Meditation (ध्यान) करें:

meditation को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। मेडिटेशन से हमारे शरीर में विशेष परिवर्तन होते है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाएँ ऊर्जा से भर जाती है , शरीर में ऊर्जा के बढ़ने से प्रसन्नता , शांति और उत्साह का संचार होता है।

6. दिन की शुरुआत positive तरीके से करे :

हमारा सुबह का समय तय करता है, हमारा पूरा दिन कैसा होगा, इसीलिए अपनी सुबह पर ध्यान दें। आप जल्दी सोयेंगे तभी आप समय पर जग पाएंगे और अपने दिन की शुरुवात अच्छे से कर पाएंगे। अपने परिवार के साथ नाश्ता करें, अच्छे समाचार सुनें, अच्छा संगीत सुनें, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे।

7. वर्तमान में जीयें :

मन को सकारात्मक एवं मन को भटकने से बचाने के लिए वर्तमान में जीना सीखें। हमारा मन तनावग्रस्त, दुखी एवं नकारात्मक रहने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, हम में से अधिकतर लोग या तो भूतकाल में जीते है या फिर भविष्य की चिंता में। फिर यही हमारे दुखों का कारण बनता है।

8 छोटी–छोटी खुशियों का आनंद उठाये :

बड़ी खुशियों की चाहत में कभी भी छोटी खुशियों को अनदेखा ना करें। क्योंकि छोटी–छोटी जीत और खुशियों को उत्सव की तरह मनाने में आपको लाइफ जीने का मज़ा आने लगेगा। आप और भी खुश और आनंद में रहने लगेंगे।

9. स्वयं पर विश्वास करे :

एक विश्वास ही है जो लोगों को एक–दूसरे से जोड़े रखता है। वही विश्वास हमें खुद पर भी होना चाहिए। नकारात्मक लोग कभी खुद पर विश्वास नहीं करते। वे हमेशा इस तरह की बातें कहते है " मुझसे नहीं होगा ये, मेरे बस की बात नहीं है " वहीं सकारात्मक लोग खुद पर विश्वास रखते है।

10. खुद को समय दें :

खुद को सकारात्मक रखने के लिए थोड़ा समय खुद को भी दें, कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताऐं , खुद को जानें , अपनी कमियाँ एवं मजबूतियों को पहचानें। जब आप एकांत में थोड़ा समय बिताएँगे, एक अलग सुकून और शांति का अनुभव करेंगे। जिससे आपका मन प्रसन्न एवं सकारात्मक रहेगा।

साभार : ऑन लाइन

Five Years of Modi Regime

When there was a feeling of ill governance across the country, as demonstrated by a number of procession rallies and dharnas, the advent of Modi government was conceived as the probable solution for the insensitivity of government machinery. Such aspiration gradually started to strengthen in the mind-frame of people of the Republic of India and some miracle were anticipated on immediate induction of the government, besides some fear at the end of some anti-nationalists. Common people, with their honest expectations, started rejuvenating their thoughts and welcomed the newly emerged political system for the advent of a new political era. As the people were mostly indifferent to the rigidity of the bureaucratic setup of our nation, which had evolved since Independence, nevertheless, they were eager to see remedial change for their decade-long issues. People were hoping to see the state as a saviour of its citizens which functions with transparency and accountability, irrespective of the political compulsion in governance.

On the other hand, Modi government also seems to have tried its best to tackle the deep-rooted problems of our country within the given resources and limitations, keeping in mind the low mandate of the ruling party in the Rajya Sabha.

The overall performance of the regime can be classified in three areas; as a performer, as an ill-performer and as a spectator.

As a Performer, Modi government tried to create "Zero Tolerance" in terms of corruption in which it succeeded to a significant extent and this was perhaps the first-ever euphoric feeling which the Indians had been struggling to have since Independence. During the year 2011, Transparency International in its Corruption Index gave India 95th rank, the lowest in India's history. But after Modi government came to power, India's rank began to improve gradually with 78th position in 2018.

Though corruption in our country is blood-mixed because of its continued sheltering for years and it is difficult to think of its complete eradication until there is a special awakening (as was found during freedom movement) in the citizens for inculcating ethics and values in their character. Therefore, the intention of the government has been a welcome step.

The second exemplary achievement of the government has been its efforts to present India as an effective contributor at the international fora. The significant improvement in the image of India at in United Nations and other international, as well as regional fora, has been witnessed by the world. Majority of the countries signed up for extended bilateral relations, including promotion of commerce, during the tenure of Modi government. After the U.S.A., Russia and China, the world has been seeing India as an emerging economic power centre. The Indian diaspora has also gained confidence that India is no more a county of poverty, corruption and ill governance, but is evolving as the country of the 21st century.

The third important achievement bagged by the government is to create an enabling environment for the promotion of enterprises and creating the legion of skilled and empowered youth. Though it may take time to plug the loopholes, the overall performance in this area can be rated as exceptional which is coupled with digital promotion. The digitization has, to a large extent, eased the lives of the people. The task which used to take 3-6 months have become doable even in weeks; this has been instrumental in bringing better governance and has created trust towards the government machinery in people's mind.

As an Ill-Performer, the Modi government tackled the reservation issue with biased intention even by neglecting the intention of the Supreme Court and no awakened society can welcome such an irrational decision. The country has already gone through the unbearable loss on many levels due to the reservation over several decades since it was brought into effect to facilitate the upliftment of the marginalised class, though the results have been mixed. Most Indians support economy-based reservation but the government used its full vigour to retrogress the country with its ill-informed policy which seems to be poorly conceived and implemented. This might be the political compulsion of the ruling party, keeping elections in mind, but it created ill-will in the intelligentsia of the country. India had suffered a lot by labelling people on the basis of castes and creeds for ages, can we still afford to remain divided on such superficial grounds and lose our original identity as similar human beings? Why cannot we work towards creating a caste-free society in the 21st century? Historically, this social evil has been a curse on the society and has created disparity among people as the generations have witnessed its tyranny during the nineteenth and twentieth centuries, which was then exploited and used as a weapon by the British to further weaken India and create hurdles in our struggle for independence.

The second big failure of the government is at the defense end. Unlike earlier governments, the Modi Government was expected to have the determination and strength to take a tough stand against terrorism and militancy. Had the security forces given full autonomy from day one to tackle militancy in the country, especially in Jammu and Kashmir, the situation would have been different before us today. Though the government tried to bank on surgical and air strikes, these kinds of operations used to be kind of the routine reactions of our forces in silence during other government tenures. But this time it was advertised widely and freely to the media and through them to the public. The Modi government also acted like the previous governments and became insensitive, except for the recent step taken to give autonomy to forces at the end of its five-year tenure. Until we as a nation treat the killing of even our single soldier or hundred soldiers as equal, such kind of insensitivity will persist. We need to be committed to saving even a single life since an individual's loss is equal to the loss of an entire kingdom because an individual is a kingdom in himself. The government failed to create an environment and a powerful image of India where no one dares attack us. Much is still needed to be learnt from countries like Israel which, despite its puny geographical area, resources and being surrounded by enemy states on all sides, is viewed as a strong nation having the capability of annihilating its enemies.

The third area of concern is the farmers' conditions coupled with the shelter-less population. Despite launching various schemes and making provisions, the most hardworking class of India is still struggling a lot on various fronts. The situation does not seem to have improved enough where we can ascertain zero suicide of farmers. A significant number of people in our country are still struggling for **"Roti, Kapda aur Makaan".** No state can afford to let its people live on their own fate sans the availability of the most essential things to survive. This has always been a distant priority and needs attention. Though some initiatives were taken in this direction but they were not enough to tackle the issue permanently. There is an urgent need to introduce a "National Policy on Safe Food" to promote organic farming. The poisonous agricultural crops are creating health hazards and we all are becoming spectators and victims. We could have learnt the lesson from our neighbours like Bhutan but the government got more occupied with "Jod-Tod" to form governments in different states even when in minority. Hence the people living under the open sky with God's mercy might have lost the "kripadrishti" of the Kings.

As a Spectator, the Modi regime tried to play safe by being diplomatic and reasonable even against the expectations of around 70 per cent of our population. Article 370 has been the agenda of the ruling party but it did not move even single inch in this direction despite the fact that it required only the ordinance not the legislation from central houses. We as a country did not have the courage or the will to remove it and save the lives of people in Jammu and Kashmir who have been living in the world of illusion and trying to protect it.

The Uniform Civil Code is an essential need of any nation. It is only in India where people are treated differently by law based on their caste, creed, religion and region. This was one of the most needed initiatives the government was supposed to take. But it did not even dare to talk on this. We have been neglecting the interest of the nation by trying to please the people who matter for the ruling parties.

The same went on in the case of Ram Janam Bhoomi as well in the name of being Sub Judice. We as a system are the victims of 'Confused-State-Of-Mind' and can "afford" to wait for decades to legally prove even the existence of air, the cosmos; ignoring the cosmic laws, law of the land and law of natural justice. This state of mind had been emaciating us internally which resulted in our slavery for ages and we seem to be heading towards the same. It is a known and accepted truth that justice delayed is justice denied and we have made the procedural things so complicated that it is difficult to come out of the cobweb knitted by us. Isn't it judicious to expect from the leaders to simplify the system and move ahead fast? Time is something which is given to us by nature without any limitations. Today's lack of initiative on our part will impact our generations tomorrow. The role of the government is to create a conducive environment for peaceful living and inclusive growth. Hence all such aspects detrimental to this holistic progress need to be tackled first.

No one can take such historic decisions with the want of power and lust of Chair. Unlike earlier governments struggling to survive amongst various afflictions, the Modi government had exhibited strong determination towards nationalism, hence the creation of exceptional expectations in Indians was inevitable. Unfortunately, the country will have to wait for another era of "Kalki's Avatar" to completely cleanse the system. The governments will come and go, but unfortunately, the problems will remain as they are. The generations will continue to be born, suffer and then perish without any instrumental change or improvement in the system. We seem to have been repeating history time and again without learning any lesson from it.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त हुआ आम आदमी

शिक्षा के साथ–साथ बच्चों के भविष्य का भी व्यापार कर रहे हैं निजी स्कूल

फीसें, किताबें और वर्दी के अलावा बाहरी खर्चों का बोझ डाल कर मालालाल हो रहे हैं ये स्कूल

शिक्षा हमारा मूल अधिकार है । एक समय था जब गुरुकुल की शिक्षा प्रकृति के सानिध्य में भारत की स्वर्णिम परंपराओं के अनुकूल प्रदान की जाती थी । उस शिक्षा में ज्ञान, संस्कार, शास्त्र, विज्ञान, तकनीकि और सामाजिक समस्त विधाओं में शिष्य को पारंगत किया जाता था । समय ने परिवर्तन की अंगड़ाई ली और धीरे–धीरे शिक्षा का स्तर समाज के साथ–साथ अपनी शैलीनुरुप बदलता गया । हमारे देश में सरकारी स्कूलों का यदि इतिहास देखें तो इस देश की उन्नति में सरकारी स्कूलों से निकले मोती वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके हैं । लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगिता के परिदृश्य में एक दौर ऐसा भी आरम्भ हुआ जिसमें शिक्षा को निजी स्कूलों की चारदीवारी में बंद कर भविष्य सुधारने का संकल्पित प्रयास लोगों की आवश्यकता ही बन गया । यहीं से शिक्षा में निजी स्कूलों की होड़ आज देश के होनहारों के लिए अनिवार्यता बनती जा रही है । निःसंकोच, निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों से अधिक माना जाने लगा है किंतु इस विचार और होड़ ने शिक्षा का खुला व्यापार भी आरंभ कर दिया । देखते ही देखते ऐसी परिस्थियां बन गई हैं कि लोग अपने बच्चों के भविष्य को औरों की देखदेखी में सुनहरा करने के प्रयास में निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आतुर हैं और निजी स्कूल इसी का फायदा उठा कर अब निचोड़ने पर आतुर हैं ।

फीस वृद्धि से परेशान अभिभावक

हर साल बच्चों की फीस वृद्धि से अब अभिभावक इतने परेशान हो चुके हैं कि इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं । यहां तक कि निजी स्कूलों की मनमानी के ख़िलाफ सड़कों पर उतर आए हैं । यह कहना उचित होगा कि निजी स्कूल न तो नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही सरकार के दिशा–निर्देशों की अनुपालना हो रही हैं । हर वर्ष फीस वृद्धि गले की फांस बनता जा रहा है । इसी फीस वृद्धि से निजी स्कूलों की करोड़ों की कमाई का धंधा भी ज़ोरो पर हो रहा है । जो बच्चा इन स्कूलों में 15 हज़ार फीस पर प्रवेश हुआ था आज उसी कक्षा में लगभग 50 से 60 हज़ार एक बारगी ही लिया जा रहा है । किस आधार पर ये फीसें बढ़ाई जाती है इसका पूर्ण विवरण तो स्कूल प्रबंधन के पास भी नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा सरकार को मांगी गई रिपोर्ट देने में आनाकानी इस बात को स्पष्ट करती है कि दाल में कुछ तो काला हैं ।

पुस्तकों, कॉपियों और स्कूल वर्दी और गाड़ियों के खर्चे का गोरखधंधा भी खुलेआम

स्कूल बच्चों से भारीभरकम फीसें ही वसूल नहीं कर रहा है बल्कि स्कूल में ही पाठ्य पुस्तकों की बिक्री कर ये शिक्षण संस्थान दुकानों में बदल गए हैं । स्कूल किताबों और कॉपियों आदि को या तो स्वयं स्कूल में ही बेचता हैं अथवा बड़े दुकानदारों के साथ सांठगांठ कर अभिभावकों को एक ही दुकान पर खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं । ये किताबें और कॉपियां आदि दो गुने से भी अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं और प्रशासन साईलैंट मोड़ पर बैठा है । एक कोट, कमीज या ट्रैक सूट तीन गुने दाम पर बेचा जा रहा है तथा उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं । वहीं बच्चों को स्कूलों से लाने ले जाने के लिए गाड़ियों में भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं । छोटी सी वैन में भी बच्चों को ठूंस–ठूंस कर भरा जाना इसको तसदीक करता है । इस मनमानी पर प्रशासन कार्यवाही की बात कर किनारा कर लेता हैं । निजी स्कूलों को यह अधिकार किसने दिया कि वो बच्चों की स्कूल की सामग्री को स्कूलों में बेचने या मनमुताबिक ऐजेंटों से खरीदने के लिए विवश करें ?

भ्रमण या किसी छोटे–बड़े कार्यक्रम हेतु पैसों की डिमांड भी आम

स्कूल एक रुपया भी खर्च किए बिना स्कूल की हर छोटी–बड़ी गतिविधियों के लिए अभिभावकों पर निर्भर हो चुके हैं । बच्चे से आए दिन अनावश्यक रुप से ही खर्चे मंगवाए जाते हैं । इतना ही नहीं एक छोटी सी क्लास फोटो के लिए भी कीमतें बढ़ाकर बच्चों से वसूल की जा रही है । करोड़ों–अरबों में खेल रहे ये निजी स्कूल एक 10 रुपये की फोटो भी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को नहीं दे पाते हैं । यह खुली लूट नही तो और क्या है ? भ्रमण के नाम पर हज़ारों रुपये ले लिए जाते हैं तथा उसका विवरण कुछ भी नहीं दिया जाता है ।

सरकार की सख़्ती सिर्फ दिखावे की

सरकार समय–समय पर ब्यान देती है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सख़्त रवैया अपनाया जाएगा लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ असरकारक क़दम नहीं उठाए जा रहे हैं । सैंकड़ों निजी स्कूलों से फीस वृद्धि और अन्य मसलों पर रिपोर्ट तलब की गई थी जिसमें से लगभग अभी तक चंद स्कूलों की ही रिपोर्ट सरकार के पास आ पाई और बाकि स्कूल सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं ।

सरकारी बनाम निजी स्कूल

एक तरफ प्रतियोगिताओं की दौड़ में निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की होड़ है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों का ढांचागत विकास काबिले तारीफ है । विशेष रुप से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सरकारी स्कूलों में भवनों और बैठने की व्यवस्था निजी स्कूलों से कहीं बेहतर स्थिति में दिखाई देती है । बच्चों के लिए छोटी कक्षाओं से लेकर माध्यमिक स्तर तक भोजन, पुस्तकें, वर्दी आदि की निःशुल्क व्यवस्था अभिभावकों को बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने के लिए पर्याप्त कहीं जा सकती है । वहीं बेहतर अध्यापकों का होना भी सरकारी स्कूल को निजी स्कूलों से पृथक करता है । लेकिन पढ़ाई का स्तर फिर भी निजी स्कूलों से कहीं न कहीं औसतन पिछड़ जाता है और लोगों की मानसिकता यही रहती है कि निजी स्कूलों में बच्चों को विकास तीव्र और गुणवत्तात्मक तरीक़े से होता है । निजी स्कूलों में अध्यापकों को बेशक वेतनमान के नाम पर ठगा जाता हो परन्तु वहां बच्चों को पढ़ाने और अंग्रेजियत की चकाचौंध का मायाजाल भ्रमित करता है । इतना ही नहीं बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही किताबों और प्रतियोगिता के बोझ तले दबाया जा रहा है ।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

आधी आबादी – अधूरा प्रतिनिधित्व, आखिर क्यों ?

महान देश भारत जहां करोड़ो लोगों की सुरक्षा की कमान एक महिला के हाथ में हो और वैश्विक ताकतों के साथ साथ किस स्थिति में कैसे पेश आना है यह भी एक महिला तय करती हो, उस देश की राजनीति में महिलाओं को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए आत्ममंथन करने जैसा है। देश में 17वीं लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो इस पर एक विशलेषणात्मक चर्चा या यू कहें कि एक टिप्पणी वाजिब है।

हमारा महान देश भारत जहां महिलाओं को आधी आबादी की संज्ञा दी जाती है और रक्षा, विदेश, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, पेयजल एवं गंगा स्वच्छता और महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा इसी आधी आबादी से ताल्लुक रखने वाली धाकड़ महिलाओं के कांधों पर है। निर्मला सीतामरमण , सुष्मा स्वराज, स्मृति ईरानी, हमसिमरत कौर, उमा भारती और मेनका गांधी, भारत की राजनीति में ये वो नाम है जो आज देश ही नहीं विदेशों में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश की राजनीति में महिलाओं का मुकाम यह सुखद है।

लेकिन क्या महज आधा दर्जन महिलाओं का यह मुकाम आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व देने जितना सुखद है.....यह सवाल इसलिए कि दो माह बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राजनीति में महिलाओं का ग्राफ किस रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा है यह आसानी से साफ हो जाता है।

वर्तमान में 543 सीटों वाली 16वीं लोकसभा में 66 महिलाएं लोकसभा में है। यानि महज 12 फीसदी। अब जब 17वीं लोकसभा के चुनावों की तिथि घोषित हो चुकी है तो एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि इस बार कहां कितनी महिलाओं पर राजनीतिक पार्टियां विश्वास जताएंगी। बीते लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो उम्मीद्वारों की फेहरिस्त में महिलाओं की संख्या महज खानापूर्ती जैसी ही दिखती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, सभी ने तंगदिली ही दिखाई है महिलाओं को टिकट देने में।

16वें लोकसभा चुनाव में वर्ष 1984 (64.01 फीसदी) के बाद देश में पहली बार 66.4 फीसदी रिकार्ड मतदान हुआ है। 2014 में जब चुनाव हुए तो लोकसभा में 61 महिलाएं चुनकर आई। उसके बाद उपचुनाव के चलते वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 66 पहुंच गई है। जबकि 15वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 59 था। आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12 फीसदी है और बड़ी बात यह है कि इस बार महिलाओं को महत्त्वपूर्ण मंत्री पद मिले हैं। इससे पहले महिलाओं को अहम पद के लिए तरजीह नहीं दी जाती थी। वर्ष 1952 में पहली लोकसभा में कुल 4.9 फीसदी महिलाएं थीं। वर्ष 1957 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 39 प्रतिशत था, जब कि पुरुषों का 56 फीसदी। वर्ष 2009 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55.8 फीसदी था और 2014 में 65.7 प्रतिशत रहा यानी पहली लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक कुल 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश में जिस रफ्तार से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उस रफ्तार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ सका है। लोकसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में बात हिमाचल की करें तो यहां भी स्थिति इत्तर नहीं है। हिमाचल की राजनीति में महिलाओं की काबलियत से ज्सादा उनके रसूख को तव्वजो दी जाती रही है।

1952 में पहले लोकसभा चुनावों में राजकुमारी अमृत कौर मंडी–महासू संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर आईं और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह वर्ष 2004 और वर्ष 2014 में मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। वर्ष 2004 में प्रतिभा सिंह चुनाव जीती थीं और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रतिभा सिंह हार गई थीं। वर्ष 1984 में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चंद्रेश कुमारी चुनी गईं। इस तरह आज तक कुल तीन महिलाएं ही लोकसभा पहुंच पाई। इसे भी राजशाही और राजनीति के गठजोड़ का नतीजा कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

सनद रहे कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में कुल चार महिलाओं ने चुनाव लड़ा। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कुल 12 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें मात्र एक महिला सुश्री आरती सोनी शिवसेना की उम्मीदवार थीं। हमीरपुर से कुल 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिनमें उर्मिला शर्मा, समाजवादी पार्टी और कमलकांत बतरा आप की उम्मीदवार थीं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल नौ उम्मीदवारों थे जिनमें एकमात्र महिला प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। शिमला संसदीय क्षेत्र से कुल सात लोगों ने चुनाव लड़ा, जिनमें एक भी महिला नहीं थी।

अब जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है तो राजनीति के गलियारों में फिर चर्चा होने लगी है कि महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियां इस बार महिलाओं पर कितना विश्वास जताएंगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी इस बार 46 प्रतिशत तक महिलाओं को टिकट देगी। यानि यह आंकड़ा आरक्षण के उस 33 फीसदी से अधिक है जिसे दिलाने के लिए बिल तो आता है लेकिन पास नहीं हो पाता। हालांकि इस बार कुछ कार्यक्रमों में कांग्रेस की ओर से बयान भी आए कि हो सकता है कि इस बार चारों सीटों पर महिलाओं को ही टिकट मिले। लेकिन यह बयान ज्यादा और हकीकत कम है। बहरहाल यह जमीनी हकीकत है कि आरक्षण से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में अपना दबदबा कायम करने के लिए जरूरत अपनी काबलियत दिखाने की है। उन महिलाओं को आगे आना होगा जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों के साथ साथ समाज और देश के विकास में योगदान देने की क्षमता रखती है। यह राजनीतिक पार्टियों का भी दायित्व है कि उन सशक्त महिलाओं को आगे लाए जो देश की दशा और दिशा बदलने का माद्दा रखती हों। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज वो नाम है जो महिलाओं को आगे लाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की इच्छाशक्ति को प्रबल बनाती है।

किस पार्टी से कितनी महिलाएं 16 वीं लोकसभा में

भाजपा	32
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	12
एआईएडीएमके	4
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	4
बीजद	3
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	2
अपना दल	1
भाकपा(मा)	1
लोजपा	1
राकंपा	1
रालोद	1
शिअद	1
सपा	1
शिव सेना	1
तेरासं	1

अंजना ठाकुर, सहायक संपादक
anjna@iirdshimla.org

छह माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी करे सरकार: हाईकोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने 1490.65 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार के असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट को दी।

अदालत को बताया गया कि नेशनल हाईवे के किनारे शौचालय बनाने और अन्य सुविधाए प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने उक्त राशि स्वीकृत की है और प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को इसके रख रखाव जिम्मा सौंपा है।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नेशनल हाईवे पर शौचालय बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी लेकिन किसी भी प्रथम श्रेणी के ठेकेदार ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

हिमाचल के तीन जिलों में चुनाव का जिम्मा संभालेगी पैरामिलिट्री फोर्स

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन भी चुनाव के लिए तैयार हो गया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा–व्यवस्था को मुस्तैद बनाने के लिए पुलिस रेंज नॉर्थ जोन कांगड़ा में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात होंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आगामी एक–दो दिन में जिला कांगड़ा, चंबा और ऊना के मतदान केंद्रों पर तैनात हो जाएंगे। पुलिस रेंज नॉर्थ जोन कांगड़ा को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी मिल चुकी है।

ऊना के 25 निजी स्कूल डिफाल्टर घोषित किए, ये है वजह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिक्षा विभाग ने जिले के 25 निजी स्कूलों को विभागीय कार्य समय पर न करने तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर डिफाल्डर घोषित कर दिया है।

शिक्षा विभाग इन निजी स्कूलों को बार–बार निर्देश जारी कर सत्र 2018–19 और 2019–20 की विद्यार्थियों से ली फीस और फंड की रिपोर्ट मांगी थी।

जिले के 96 से 71 स्कूल ने कुछ दिन देरी के बाद रिपोर्ट जमा करवा दी। बाकी स्कूलों ने अभी तक भी विभाग के निर्देशों को नहीं माना। इसके चलते शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए डिफाल्टर घोषित कर दिया है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि डिफाल्टर स्कूलों की रिपोर्ट बनाकर वह शिमला निदेशालय भेजेंगे। इसके बाद इन निजी स्कूलों को चलाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मिलने वाली एनओसी रद्द कर दी जाएगी।

लोकसभा चुनाव में इन चेहरों पर दांव खेल सकती है हिमाचल कांग्रेस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव का एलान होते ही हिमाचल कांग्रेस ने प्रत्याशियों को तय करने की कवायद तेज कर दी है। चारों सीटों से पार्टी टिकट के लिए 40 नेताओं ने आवेदन किया है लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी आवेदन का पैमाना छोड़कर जिताऊ चेहरों पर दांव खेल सकती है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी जल्द इस पर फैसला लेगी। इसके बाद नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी। सूत्रों के अनुसार शिमला संसदीय सीट को छोड़कर अन्य तीनों सीटों पर आवेदन न करने वालों को टिकट दिया जा सकता है।

शिमला में शांडिल, सुल्तानपुरी और नंदा दौड़ में आगे

शिमला संसदीय सीट (आरक्षित) से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को माना जा रहा है। वे दो बार सांसद रह चुके हैं।

युवा नेता विनोद सुलतानपुरी भी आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने दो बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए।

हिमाचल में इस बार अप्रैल से लागू नहीं होंगी बजट की कई घोषणाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनावों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने से प्रदेश में कई प्रोजेक्ट और विकास कार्य लटक गए हैं। बड़ी बात यह है कि अधिसूचना न होने की वजह से इस बार बजट की कई घोषणाएं अप्रैल महीने से लागू नहीं हो सकेंगी।

यही नहीं, बीते 15 दिन के भीतर जयराम सरकार ने तीन बार कैबिनेट बैठकें की हैं, जिनमें कई फैसले लिए गए हैं। लेकिन अधिसूचना न होने की वजह से ये फैसले चुनाव पूरे होने तक धरातल पर नहीं उतर सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में 40 नए शिक्षण व चिकित्सा संस्थानों को खोलने व अपग्रेड करने को मंजूरी दी थी। इसमें प्राथमिक पीएचसी और सीएचसी, सिविल अस्पताल और अधिकांश अस्पतालों को 50 से 100 बिस्तर किए जाने की घोषणा की गई थी।प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में 40 नए शिक्षण व चिकित्सा संस्थानों को खोलने व अपग्रेड करने को मंजूरी दी थी। इसमें प्राथमिक पीएचसी और सीएचसी, सिविल अस्पताल और अधिकांश अस्पतालों को 50 से 100 बिस्तर किए जाने की घोषणा की गई थी।

सुबाथू सैन्य छावनी में फिर लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय सेना के गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू से सटे छावनी क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद, जैश–ए–मोहम्मद और आईएसआई के नारे लिखे मिले हैं। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

स्थानीय लोगों ने सैन्य छावनी के साथ लगते निजी स्कूल के बोर्ड पर ये नारे लिखे देखे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी । पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और देशद्रोह का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ नारों को मिटाने की कोशिश भी की गई थी। इन नारों के बीच अलर्ट शब्द भी लिखा गया है। खास बात यह है कि बोर्ड पर उर्दू में यह सब लिखा है।

स्कूल प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। डीएसपी परवाणू की अगुवाई में एक टीम ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने मामले में आसपास के कुछ ग्रामीणों से भी पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी 102 साल की उम्र में करेंगे मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी 102 वर्ष की उम्र में लोकसभा चुनाव–2019 में मतदान करेंगे। नेगी ने आजादी के बाद वर्ष 1952 में पहली बार आम चुनाव से पूर्व 23 अक्तूबर 1951 को जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में वोट डाला था।

दिलचस्प है कि भारी बर्फबारी के चलते किन्नौर में देश के चुनावों से पूर्व विशेष मतदान कराया गया था। ऐसे में आम चुनाव के लिए उस समय श्याम सरन नेगी ने देश का पहला वोट डालकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया था।

प्रथम मतदाता नेगी इस बार भी कल्पा के बूथ नंबर 51 में पहुंचकर 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। आगामी जुलाई 2019 को 102 वर्ष के होने जा रहे कल्पा निवासी श्याम सरन नेगी ने युवाओं से जांच परख कर मतदान करने की अपील की है।

गौरतलब है कि देश के प्रथम मतदाता श्याम सरण नेगी ने मिशन रीव के सदस्यता ली है ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मौके पर निपटाए 3655 मामले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य में लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने को प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालयों में प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया।

लोक अदालतों में कुल 8857 मामलों को आपसी समझौते के लिए लिया गया। इनमें 3755 पूर्व मुकदमेबाजी व 5102 लंबित मामले थे। इन्हें निपटाने को विभिन्न बेंचों में रखा गया। 3655 मामले जिसमें 943 पूर्व मुकदमेबाजी व 2712 लंबित मामों का निपटारा आपसी समझौते से किया गया।

तेरह करोड़ उनसठ लाख उन्यासी हजार नौ सौ छियासठ रुपये का मुआवजा भी पक्षकारों को दिलाया गया। लोक अदालत में लगभग 1119 ग्राम पंचायतों व नगर परिषदों के मुकदमे निपटाए गए।

हिमाचल : 7 प्रदूषित शहरों में अप्रैल से डीजल वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर रोक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के 7 प्रदूषित शहरों में अगले महीने से डीजल वाहनों के पंजीकरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। पहले चरण में ऑटो रिक्शा और टैंपों जैसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है । इसके तहत सोलन जिला के बद्दी, नालागढ़, परवाणु, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, कालाअंब, कांगड़ा जिला के डमटाल और मंडी जिला के सुंदरनगर में इस आदेश के तहत डीजल वाहनों की रिजस्ट्रेशन नहीं होगी।

दूसरे चरण में अन्य डीजल वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाने की तैयारी है। इन शहरों में 15 साल पुराने डीजल वाहनों की पासिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इन्हें भी सड़कों पर चलने से रोकने की तैयारी कर दी गई है। इन 7 शहरों में 15 साल व इससे पुराने डीजल वाहनों की शहर के अंदर एंट्री बंद करने की तैयारी है।

शहर के बाहर अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर ही यह वाहन गुजर सकेंगे। आने वाले समय में इन्हें भी सड़कों पर चलने से रोकने की तैयारी कर दी गई है। गौरतलब है कि हिमाचल के पर्यावरण को लेकर एनजीटी समय–समय पर सरकार को चेताती रही है ताकि प्रदेश को प्रदूषण से बचाया जा सके।

चारों मौजूदा सांसदों के नामों पर ही हिमाचल भाजपा में बनी सहमति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय स्तर पर भले ही भाजपा के 40 फीसदी सांसदों के टिकट कटने की बात सामने आ रही हो, लेकिन हिमाचल में पार्टी चेहरे बदलने के पक्ष में नहीं है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है।

प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की दो दिवसीय बैठक में चारों मौजूदा सांसदों को फिर मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो प्रदेश भाजपा हाईकमान को टिकट के लिए चार ही नाम भेजेगी। हालांकि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर भाजपा संसदीय बोर्ड ही लगाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी प्रभारियों और प्रदेशाध्यक्ष सहित दो दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक में लोकसभा की चारों सीटें फिर से जीतने के लिए रणनीति पर मंथन किया।

निजी स्कूलों की लूट के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी की जमकर नारेबाजी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हर वर्ष नियमों को ताक पर रखकर फीस को मनमानी तरीके से बढ़ाना । किताबों व स्टेशनरी में धांधली, वर्दियों की खरीद पर दुकानदारों से मिलीभगत का कमीशन निजी स्कूलों की फितरत बन चुकी है। लेकिन प्रदेश का शिक्षा विभाग है कि कार्यवाही करने की बजाय कुम्भकर्णीय नींद सो रहा है। ऐसे स्कूलों पर खुद नकेल कसने के आदेश जारी कर कार्यवाही करना भूल जाता है। पर अब छात्र अभिभावक मंच इसके विरुद्ध खुद आ गया है।

इसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग को गहरी नींद से जगाने के लिए छात्र अभिभावक मंच ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी भी की और राज्य शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र अभिभावक मंच के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शिमला सहित पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की लूट जारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने 1472 स्कूलों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया लेकिन सिर्फ 53 स्कूलों ने जबाब दिया। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग स्कूलों के साथ मिला हुआ है। इसलिए उनके आदेशों को स्कूल गंभीरता से नही लेते। निजी स्कूल एक बच्चे से 24 से 50 हजार सालाना फीस वसूल रहे हैं। बिल्डिंग फंड व एडमिशन फीस की लूट अलग से जारी है। न्यायालय के आदेशों सहित सीबीएसई की गाइडलाइंस को भी दरकिनार करने वाले ये स्कूल करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं।

बिना अनुमति दो बार स्ट्रांग रुम खोलने पर निर्वाचन आयोग की फटकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत निर्वाचन आयोग से बिना मंजूरी मिले दो बार स्ट्रांग रूम खोलना एसडीएम चौपाल को भारी पड़ गया। आयोग के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने एसडीएम चौपाल मुकेश रेपसवाल का तबादला विशेष सचिव शिक्षा के पद पर कर दिया है।

इसके साथ ही तहसीलदार चौपाल को एसडीएम का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। शासन के सूत्रों के अनुसार पिछले साल एसडीएम मुकेश ने दो बार उस स्ट्रांग रूम को खोला, जिसमें ईवीएम रखी थीं।

पहली बार जानकारी जिला प्रशासन को नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार अक्तूबर 2018 में जब स्ट्रांग रूम खोला तो सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। उसी आधार पर हुई जांच के बाद आयोग के निर्देश पर एसडीएम का तबादला हो गया। सूत्रों का कहना है कि एसडीएम ने स्थानीय नेताओं को बुलाकर वीडियोग्राफी कराते हुए स्ट्रांग रूम खोला, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति न लेने के चलते गाज गिर गई।

हिक्किम नहीं अब ये है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव में इस बार हिमाचल के लाहौल–स्पीति जिले का टशीगंग देश एवं दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होगा। चीन सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर 15,256 फीट की ऊंचाई पर यह पोलिंग बूथ बनाया गया है। स्पीति के मुख्यालय काजा से करीब 35 किलोमीटर दूर टशीगंग में अभी भी तीन से चार फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी है।

ऑक्सीजन की कमी एवं ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहां पेड़–पौधे तो दूर, घास भी मुश्किल से उग पाती है। टशीगंग पोलिंग बूथ में कुल 49 मतदाता हैं, जिनमें 29 पुरुष और 20 महिलाएं हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन
संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

भारतीय वैज्ञानिकों ने कवक की नई प्रजातियां खोजीं, कैंसर उपचार में लाभ का दावा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में कवक की नई प्रजातियों की तलाश की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस कवक से ब्लड कैंसर का उपचार करने में सहायता मिल सकती है। इन खास कवक प्रजातियों से ब्लड कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले एंज़ाइम एल–एस्पेरेजिनेज़ का उत्पादन किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में कवक प्रजातियों के विभिन्न नमूने एकत्रित किये थे। इनमें शामिल लगभग 30 नमूनों में शुद्ध एल–एस्पेरेजिनेज़ पाया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को देश भर में मनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 'लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग' (Science for the People and People for Science) है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी।

सीवी रमन को इस खोज के कारण वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबल पुरस्कार था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाने के लिए केंद्र सरकार को कहा था।

स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ रोज़गार के लिए तैयार करने हेतु SHREYAS पोर्टल लॉन्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिये उन्हें काबिल बनाने के लिए बीते दिनों 'श्रेयस' (स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कर उन्हें कौशल युक्त बनाया जायेगा ताकि वे रोजगार के योग्य हो सकें। प्राथमिक योजना का संचालन National Apprenticeship Promotion Scheme (एनएपीएस) के साथ किया जाएगा, जो प्रत्येक व्यवसाय/उद्योग में कुल कार्यबल के 10 प्रतिशत तक प्रशिक्षुओं को रखने का प्रावधान करता है। यह योजना शुरू में बैंकिंग कौशल बीमा सेवा (बीएफएसआई), खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, प्रबंधन सेवाओं, आईटीईएस और सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

भारत में बनेगी दुनिया की आधुनिकतम असॉल्ट AK–203 राइफल

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 03 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भारत–रूस के आयुध कारखाने का उद्घाटन किया। भारत–रूस (इंडो–रशिया) राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत की आयुध फैक्टरी और रूस के प्रतिष्ठान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। कोरवा आयुध फैक्टरी द्वारा भारतीय सेना को एके–47 राइफल का आधुनिक संस्करण AK–203 प्रदान किया जाएगा। कोरवा आयुध फैक्टरी में प्रतिष्ठित कलाशनिकोव राइफलों की नवीनतम श्रेणियां बनाई जाएंगी। यह संयुक्त उद्यम देश में शस्त्र सेनाओं को मदद देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। रूस के सहयोग से अमेठी में AK-203 मॉर्डन राइफल बनाने का काम शुरू किया जायेगा। यहां भारतीय सेना के लिए 7.5 लाख राइफलें बनाई जायेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय स्मारक के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना विज़न प्रस्तुत किया था। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बने इस युद्ध स्मारक की लागत 176 करोड़ रुपये आई है और यह रिकार्ड एक साल में बनकर पूरा हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन कार्ड योजना जारी की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 04 मार्च 2019 को स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का शुभारंभ किया। लोगों को देशभर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सेवा आरंभ की गई है। अलग–अलग परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले 'एक राष्ट्र एक कार्ड' से धारक अपनी बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीददारी कर सकेंगे और यहां तक कि पैसा भी निकाल सकेंगे. इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, बस, उप नगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा दुकानों में भी किया जा सकेगा।

न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में आतंकी हमला, 49 लोगों की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च नामक स्थान पर दो मस्जिदों में एक अज्ञात बंदूकधारी द्वारा भीषण फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 49 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि हमलावर ने घटना की लाइव वीडियो भी बनाई थी।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न द्वारा मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई। उनके द्वारा कहा गया कि यह न्यूजीलैंड के इतिहास में 'काला दिन' है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूजीलैंड की अल–नूर मस्जिद तथा लिनवुड मस्जिद को निशाना बनाया गया था।

द रीव टाइम्स संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा फोन न. 0177 2640761, मेलः editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 इंदौर लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 06 मार्च 2019 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर को लगातार तीसरे वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन पुरस्कारों की स्थापना केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण–2019 के तहत कुल 70 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गये। सबसे स्वच्छ शहर के साथ ही स्टार रैकिंग और ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट का पुरस्कार भी इंदौर को मिला। वहीं, मध्यप्रदेश को कुल 19 पुरस्कार मिले हैं।

20 रुपये का सिक्का जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 20 रुपये का सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 07 मार्च 2019 को 20 रुपये के नए सिक्के के अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का नया सिक्का भी जारी किया है। यह 20 रुपये का सिक्का दिव्यांग, विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वे भी इसकी विशेष फीचर्स के चलते इसे पहचान सकेंगे। सिक्कों की अलग–अलग विशेषताओं के चलते यह दिव्यांग लोगों को भी आसानी से पहचान में आ पाते हैं।

मेनका गांधी ने 30 महिलाओं को 'वेब वंडर वुमन' पुरस्कार प्रदान किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 06 मार्च 2019 को सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपब्धियों को मनाने के लिए आयोजित अभियान वेब वंडर वुमेन का अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के बाद 30 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने सम्मानित किया।

ट्विटर इंडिया तथा ब्रेकथ्रू इंडिया के सहयोग से आयोजित इस समारोह का उद्देश्य विश्व की उन भारतीय महिला हस्तियों की दृढ़ता और साहस को मान्यता देना है जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सार्थक अभियान चलाने में सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है।

गृह मंत्रालय ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट–फेंसिंग' लॉन्च की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 06 मार्च 2019 को भारत–बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग (बाड़) सिस्टम की शुरुआत की। असम के धुबरी जिले में भारत–बांग्लादेश सीमा पर इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। लगभग करीब 61 किलोमीटर लंबे इस सीमावर्ती इलाके में भारत–बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत 'बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यू–आई–टी सिस्टम (BOLD & QIT) की शुरुआत के बाद से भारत बंग्लादेश सीमा पर कई तरीके के अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या विवाद में होगी मध्यस्थता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यों का पैनल गठित किया है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचु भी पैनल में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की रिपोर्टिंग न की जाए। कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता करने वाले तीन सदस्यीय पैनल को 4 हफ्तों में अपनी शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी और 8 हफ्तों में अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। कार्रवाही फैजाबाद (अयोध्या) में होगी और गोपनीय होगी।

परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन स्वीकृत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 07 मार्च 2019 को स्वच्छ, साझा, सतत एवं समग्र गतिशीलता पहलों को बढ़ावा देने के लिए 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' की शुरुआत करने को स्वीकृति दी गई है। भारत में कुछ व्यापक निर्यात–प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले एकीकृत बैटरी एवं सेल–निर्माता गीगा संयंत्रों की स्थापना में सहयोग देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के लिए मान्य है। इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी समूची मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में होने वाले उत्पादन के स्थानीयकरण के लिए पीएमपी बनाने को मंजूरी दी गई है जो वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के लिए मान्य है। दोनों ही पीएमपी योजनाओं को 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

अमेरिका ने भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 04 मार्च 2019 को ये फैसला लिया है कि वह भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे, जो सामान्य कर–मुक्त प्रावधानों (जीएसपी) कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है।

अमेरिका ने भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है। यह घोषणा उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद हुई है जिनके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को पत्र लिख कर अपने इस कदम के बारे में अवगत कराया है।

विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए 137 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत छह राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये 137 मिलियन डॉलर (लगभग 960 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान किया है। यह बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित है। पूर्व में विश्व बैंक ने डीआरआईपी के तहत वित्तपोषण के लिये 350 मिलियन डॉलर (लगभग 2450 करोड़ रुपए) की मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ईस्ट ऑफ़ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद्भागवत गीता का विमोचन किया। इस्कॉन संस्था द्वारा तैयार की गई विश्व की सबसे बड़ी गीता इटली के मिलान शहर में बनाई गई है। इस अवसर पर उन्होंने 800 किलो की 670 पृष्ठों वाली विशाल गीता का विमोचन किया तथा लोगों को संबोधित भी किया।

इंडियन रेलवे ने नई वेबसाइट रेल दृष्टि लॉन्च की

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल यात्रियों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया, जिसे वे ट्रेन के आने–जाने के समय पर निगरानी के साथ–साथ देश में कहीं भी ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। डैशबोर्ड को लॉन्च करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अब लोग कहीं भी जाते समय मात्र एक स्वाइप पर भारतीय रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकते हैं। यह डैशबोर्ड यात्रियों, रेलवे के अधिकारियों व स्टाफ के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके जरिए यात्री रेलवे से जुड़ी हर तरह की जानकारी अब एक स्वाइप से प्राप्त कर सकेंगे। 'रेल–दृष्टि' डैशबोर्ड को रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) द्वारा विकसित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को एक औपचारिक समारोह के दौरान राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को भी संबोधित किया। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं। यह कार्यक्रम दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की चार परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देशः SIPRI रिपोर्ट

स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

बच्चे को एयरपोर्ट पर छोड़ प्लेन में चढ़ गई मां, उड़ान भरने के दौरान हुआ कुछ ऐसा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सऊदी अरब एयरलाइन के एक विमान को उड़ान भरने से रुकना पड़ा क्योंकि एक महिला यात्री हवाईअड्डे पर अपने बच्चे को भूल गई थी । टेलीग्राफ डॉट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में सवार महिला को जब याद आया कि वह अपने बच्चे को साथ लाना भूल गई है तो उसने इसके बारे में पायलट को सूचित किया।

इसके बाद कुआलालम्पुर जाने वाले विमान को सऊदी अरब के जेद्दा में किंग अब्दुलअजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के अपने द्वार पर लौटना पड़ा ।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगते हुए पायलट का एक वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है । वह बड़बड़ाते हुए सुनाई दिया, 'भगवान हमारे साथ रहे । क्या हम वापस आए या नहीं.'

इससे भी ज्यादा हैरानी कि बात ये थी कि कंट्रोलरों में एक यह कहते हुए सुनाई दिया, ''ठीक है, द्वार पर वापस आइए । यह हमारे लिए बिल्कुल नया है ।''

दुनिया भर में बिक रही हैं निमोनिया और मलेरिया की नकली दवाएं, अब तक कुल 3 लाख बच्चों की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दुनियाभर में फैला नकली दवाओं का जाल बच्चों की सेहत के लिए संकट बनता जा रहा है। एक शोध में सामने आया है कि मलेरिया, निमोनिया व अन्य बीमारियों के इलाज के नाम पर बिक रही नकली व निर्धारित मानक से निम्न स्तर की दवाओं से हर साल हजारों बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के फोगार्टी इंटरनेशनल सेंटर के सलाहकार जोल ब्रीमैन के अनुसार ऐसी दवाओं से अब तक तीन लाख बच्चों की जान जा चुकी है, जो चिंतनीय है। अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए ब्रीमैन ने नकली दवा बेचने वालों को हत्यारा भी बताया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नकली दवाएं तीन तरह की होती हैं। एक में दवा का नाम और उसका कंपोजिशन गलत होता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, जो निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। उनमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी घटक की मात्रा कम रखी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कहीं से प्रमाणित नहीं हैं, ना ही उन्हें पंजीकृत कराया गया है। ब्रीमैन व उनकी टीम का कहना है कि वर्तमान में नकली दवाओं का व्यापार चरम पर है।

जल्दी बूढ़ा महसूस करते हैं भारतीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

जापान और स्विट्जरलैंड में रहने वालों की तुलना में भारतीयों को बढ़ती उम्र में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना जल्दी करना पड़ता है। लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोध को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है।

अध्ययन के मुताबिक, औसतन 65 साल की उम्र के होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना अलग-अलग देश के लोग अलग-अलग उम्र में करते हैं। उम्र का यह अंतर 30 साल तक पाया गया है। जापान और स्विट्जरलैंड के लोगों को ऐसी परेशानियां औसतन 76 साल में होती हैं, वहीं पापुआ न्यू गिनी के लोगों को यही दिक्कतें 46 साल की उम्र से ही महसूस होने लगती हैं। भारतीयों को इन परेशानियों का अनुभव 60 साल की उम्र से होने लगता है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है। प्रमुख शोधकर्ता एंजेला वाई चांग ने कहा, 'इन नतीजों से यह समझा जा सकता है कि लोगों की औसत आयु बढ़ते जाना हर मामले में सुखद नहीं हो सकता । अगर बुढ़ापे की परेशानियां कम उम्र से महसूस होने लगें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लंबी उम्र जीना और मुश्किल हो जाता है। समय से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण अगर लोगों को अपनी चपेट में लेने लगेंगे, तो यह कई मामलों में नुकसान का कारण बन सकता है। इससे कामकाजी लोगों की संख्या में कमी आएगी। लोग जल्दी रिटायर होना चाहेंगे। सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को इस परेशानी की गंभीरता को समझना चाहिए।'

गुड़गांव दुनिया में सबसे प्रदूषित, टॉप-5 में भारत के 4 शहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

(वॉशिंगटन) दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गुड़गांव टॉप पर है । आई क्यू एयरविजुअल और ग्रीनपीस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। वहीं दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में भारत के 7 शहर हैं। टॉप-5 में पाकिस्तान के फैसलाबाद के अलावा 4 शहर भारत के ही हैं। प्रदूषण का आकलन पी एम2. 5 कणों के आधार पर किया गया है । पी एम 2.5 कण अत्यंत महीन होते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।

टॉप 10 में भारत के 7 शहर

रैंक	शहर	प्रदूषण का स्तर
1	गुड़गांव (हरियाणा)	135.8
2	गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)	135.2
3	फैसलाबाद (पाक)	130.4
4	फरीदाबाद (हरियाणा)	129.1
5	भिवाड़ी (राजस्थान)	125.4
6	नोएडा (उत्तरप्रदेश)	123.6
7	पटना (बिहार)	119.7
8	होतान (चीन)	116.0
9	लखनऊ (उत्तरप्रदेश)	115.7
10	लाहौर (पाक)	114.7

आपके टूटे या कटे बालों की कीमत है 2000 रुपये किलो, टॉप 10 निर्यातकों में हैं भारत-पाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

घरों में सुबह-शाम जिसे हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, वास्तव में उनकी कीमत हजारों रुपये में है। पूरी दुनिया में इसका सालाना कारोबार कई अरब रुपये का है। वैश्विक बाजार में भारत और पाकिस्तान इस मार्केट के प्रमुख निर्यातक हैं। दोनों देशों में इस कारोबार पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। दुनिया के कई विकसित देश इसके खरीदार हैं।यहां हम बात कर रहे हैं, मानव बाल की। जी हां, सुनने में ये भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन मानव बाल भारत-पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था का मजबूत हिस्सा बनते जा रहे हैं। अमूमन हमरे घरों में टूटे बाल या सैलून में काटे गए बाल कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए ये करोड़ों का कारोबार और कमाई का प्रमुख जरिया है।

5800 करोड़ रुपये से ज्यादा का है वैश्विक कारोबार

यूएस और जापान, पाकिस्तान से प्रीमियम क्वालिटी के बालों के सबसे बड़े खरीदार हैं। ये देश इन बालों का इस्तेमाल अपने मनोरंजन उद्योग में करते हैं। वहीं चीन में कास्मेटिक उद्योग के बढ़ने के साथ ही मानव बालों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 के दौरान दुनिया भर में मानव बाल के निर्यात का कुल कारोबार तकरीबन 5800 करोड़ रुपये रहा था।

भारत-पाक में और तनाव बढ़ने की आशंका खत्म पाक सरकार ने इस तरह से निकाला निष्कर्ष

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पाकिस्तान सरकार के एक आंतरिक आकलन में निष्कर्ष निकाला गया है कि पुलवामा हमले के बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच और तनाव बढ़ने का जोखिम खत्म हो गया है। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार की खबर के मुताबिक दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों की मौजूदा स्थिति पर पृष्ठभूमि सहित ब्यौरे दिए जाने के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह आकलन साझा किया।

अधिकारी ने कहा, 'तनाव में साफ तौर पर कमी दिख रही है। अब इसके और बढ़ने की आशंका नहीं है।' अखबार में कहा गया कि ऐसी आशंका थी कि भारत इस संकट को और ऊपर ले जाने के लिए एक से अधिक हवाई हमले कर सकता है या स्थिति को खींच सकता है।

यह पूछने पर कि चुनाव से पहले क्या भारत द्वारा अन्य किसी घटना को अंजाम दिए जाने की पाकिस्तान को आशंका है, अधिकारी ने कहा कि भारत की ओर से ऐसी आक्रामक कार्रवाई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अखबार के मुताबिक सरकार केइस आकलन को स्पष्ट तौर पर कूटनीतिक प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें कई क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पक्ष शामिल हैं जो दोनों देश में तनाव कम होते देखना चाहते हैं।

वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष की आंच भारत तक पहुंची, अमेरिका ने किया ये अनुरोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने उम्मीद जताई है कि भारत निकोलस मादुरो से तेल नहीं खरीदेगा । पोम्पिओ और भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले की संयुक्त बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि 'हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस मामले में अमेरिकी नीति का समर्थन करेगा।' अमेरिका, वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति मादुरो के बजाय कार्यवाहक राष्ट्रपति गुएडो का समर्थन करता है।

पत्रकारों से बात करते हुए पोम्पिओ ने कहा कि भारतीय विदेश सचिव के साथ हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ईरान के मामले में हमारे प्रयासों का समर्थन करता है, मुझे विश्वास है कि वह वेनेजुएला मामले में भी अमेरिकी नीति का सपोर्ट करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत वेनेजुएला के राजनीतिक संकट के साथ-साथ वहां के मानवीय त्रास्दी को भी ध्यान में रखेगा। पोम्पिओ ने रूस और चीन का नाम लिए बगैर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का समर्थन करने वाले राष्ट्र एक अवैध सत्ता का समर्थन करते हैं।

हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं महिलाएं लेकिन राजनीति में आई गिरावट

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीतिक धरातल पर महिलाओं की स्थिति हतोत्साहित करने वाली है। विश्वभर में राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद महिलाओं की संख्या में गिरावट आई है। हाल में जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है । राजनीति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है और विश्व के नेताओं में मात्र 7 प्रतिशत और सांसदों में केवल 24 प्रतिशत महिलाएं हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि हालिया वर्षों में विश्वभर में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। अंतर-संसदीय संघ के पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने का प्रतिशत 2017 के 7.2 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 6.6 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि में सरकार में महिला प्रमुखों का प्रतिशत भी 5.7 प्रतिशत से गिरकर 5.2 प्रतिशत रह गया है।

ब्लैकमेलिंग करने के लिए दुबई कोर्ट में पहली बार महिला को ठहराया गया दोषी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दुबई में पहली बार किसी महिला को ब्लैकमेल करने का दोषी करार दिया गया है। खलीज टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, महिला पर अमीरात के एक शख्स को ब्रेकअप करने के लिए धमकी देने और पैसे मांगने का आरोप था। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में उसे दोषी करार देते हुए ईशनिंदा का भी दोषी माना। एक क्लब में डांसर का काम करनेवाली महिला ने ब्रेकअप के बाद पीड़ित शख्स पर हर महीने 4,500 दिरहम देने के लिए दबाव बनाया था।

सात हजार अतिसूक्ष्म समुद्री प्रजातियों की हुई खोज

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

शोधकर्ताओं ने प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से सात हजार नई अतिसूक्ष्म प्रजातियों की खोज की है। शोधकर्ताओं ने बताया कि उनकी यह खोज दुनिया भर के समुद्रों के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एचकेयूएसटी) के शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने समुद्र में पहली बार क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम युक्त एसिडोबैक्टीरिया सहित अन्य प्रजातियों की खोज की है। शोधकर्ताओं को यह खोज करने में आठ सालों का समय लगा। उन्होंने इस दौरान 10 बैक्टीरियल फाइला की खोज भी की।

नेचर जर्नल कम्यूनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह खोज उन बातों को गलत साबित करती है जिनमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में केवल 35 हजार अतिसूक्ष्म समुद्री प्रजातियां और 80 बैक्टीरियल फायला हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस खोज के माध्यम से समुद्र की जैवविविधता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवाएं बनाने की आशा जगी है।

पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को लेकर वैश्विक चिंता का समाधान करे : भारत-अमेरिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वह सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से निपटे और आतंकवाद संबंधी वैश्विक चिंता का समाधान करे। विदेश सचिव विजय गोखले और उनके अमेरिकी समकक्ष राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री डेविड हैल ने विदेश मंत्रालय के फॉगी बॉटम मुख्यालय में वार्ता की।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब से टकराव नहीं: OIC में सुषमा स्वराज

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ऋग्वेद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान एक हैं और सभी धर्मों का मतलब है शांति। बता दें कि OIC की मीटिंग में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर न्योता भेजा गया था।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र, उद्घाटन संबंधि समाचार आचार संहिता लागू होने से पूर्व के हैं

करंट अफेयर्स

- जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर इतना करने की घोषणा की है– 5 प्रतिशत
- ऑस्कर 2019 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है–ग्रीन बुक
- वह गायिका जिसे हाल ही में 'ए स्टार इज़ बॉर्न' के गाने शैलो' के लिए बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग केटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार मिला है –लेडी गागा
- भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म जिसे हाल ही में ऑस्कर 2019 में बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला है –पीरियड. एंड ऑफ़ सेंटेंस
- वह स्थान जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ किया गया–गोरखपुर
- वह स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित किया–नई दिल्ली
- वह खिलाड़ी जिसने ट्वेंटी–20 मैच में 4 गेंदों पर 4 विकेट हासिल किये – राशिद खान
- वह कम्पनी जिसे हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की सीआरआर अवार्ड से सम्मानित किया गया है–जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
- वह राज्य जिसने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया–गुजरात
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में इस स्थान पर अपोलेमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया –लखनऊ
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने जिस शहर में चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन का उद्घाटन किया– नई दिल्ली
- केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल और जिस राज्य के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) का उद्घाटन किया– असम
- अफगानिस्तान ने जिस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया है– ईरान
- मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली देश की एकमात्र निजी एजेंसी स्काईमेट ने 2019 में जिस देश में सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है– भारत
- दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के बजट में शिक्षा को दिया गया प्रतिशत है– 26 प्रतिशत
- दिल्ली सरकार के एंटरप्रेन्योर करिकुलम के तहत बजट भाषण में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को दी जाने वाली धनराशि है –1,000 रुपये
- हरियाणा सरकार के बजट भाषण 2019–20 में किसान पेंशन और अन्य किसान योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि है –1500 करोड़ रुपये
- हरियाणा सरकार के 2019–20 के बजट भाषण में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग को आवंटित राशि है – 211 करोड़ 30 लाख रुपये
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द द्वारा इन्हें वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है – योहेई ससाकावा
- भारतीय वायुसेना ने जिस इंडियन फाइटर जेट के जरिये एलओसी पार (पाक) आतंकियों के ठिकानों पर निशाना बनाया– मिराज–2000
- भारत की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है – QRSAM वह भारतीय जिसे हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप–10 में जगह दी गई है–मुकेश अंबानी
- प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इस्कॉन में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवदगीता का वजन है–800 किग्रा
- केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में जयपुर स्थित बगरु में ब्लॉक प्रिंटिंग के संरक्षण हेतु जिस म्यूजियम का उद्घाटन किया है – तितानवाला म्यूजियम
- केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूरी दिए गये घरों की संख्या है–5 लाख
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है– 2 साल
- भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट, चकोठी और जिस जगह में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया– मुजफ्फराबाद
- आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक और जिस बैंक को 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (पीसीए) सूची से बाहर कर दिया है– कॉर्पोरेशन बैंक
- उद्योगपति गौतम अदाणी के अदाणी समूह ने निजीकरण के लिए रखे गए सभी जितने हवाई अड्डों के अगले 50 वर्षों तक परिचालन को लेकर बोलियां जीत ली हैं–06
- अफगानिस्तान ने जिस देश की सेना के अतिक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

परिषद (यूएनएससी) में शिकायत की है– पाकिस्तानी सेना
- वेस्टइंडीज के क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 और वनडे क्रिकेट में जितने छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं–300 छक्के
- हाल ही में राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक एनपीपीए ने कैंसर, डायबिटीज़, संक्रमण, दर्द और अस्थमा समेत अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुल जितने दवाओं की कीमतें निर्धारित कर दी है–36
- भारत के सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 27 फरवरी 2019 को दिल्ली में जारी शूटिंग विश्व कप में जितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लिया–10 मीटर
- वह भारतीय विकेटकीपर–बल्लेबाज़ जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी–20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं– महेंद्र सिंह धोनी
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने हाल ही में करीब जितने रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है–2,700 करोड़ रुपये
- इन्हें हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है–गोविन्द प्रसाद शर्मा
- वह राज्य जिसने परिवार समृद्धि योजना की घोषणा की है–हरियाणा
- बधिर लोगों के लिए हाल ही में आईएसएल द्वारा जारी किये गये शब्दकोश में कुल शब्द हैं –6000
- वह कंपनी जिसके द्वारा 4जी/एलटीई और 5जी एनआर मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप्स को जारी किया गया– सिग्नलचिप
- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिये उन्हें काबिल बनाने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम है–श्रेयस
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को जिस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है– बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर
- सुप्रीम कोर्ट ने 08 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए जितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है– तीन
- जिस राज्य के राज्यपाल के. राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 08 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया– मिज़ोरम
- वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) और पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट के तहत ना आने वाले कर्मचारियों की जितने लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी टैक्स फ्री कर दी है–20 लाख रुपये
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में बक्सर (बिहार) के चौसा में 660–660 मेगावाट के जितने ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दे दी गई– दो
- एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को इस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6434 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं – वर्ष 2020
- वह राज्य जहां हाल ही में 'युवाश्री अर्पण' योजना आरंभ की गई है –पश्चिम बंगाल
- वह राज्य जहां केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कीरू पनबिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है –जम्मू–कश्मीर
- इन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार–2019 के लिए चयनित किया गया है – अराता इसोजाकी
- वह देश जिसके साथ भारत ने 10 साल के लिए पनडुब्बी लेने हेतु तीन अरब डॉलर का समझौता किया है– रूस
- वह राज्य जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार–2019 में प्रथम स्थान हासिल हुआ –इंदौर
- भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में जितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की–22
- जिस देश की संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है– रूस
- वेनेजुएला की सरकार ने जिस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है– जर्मनी
- वह शहर जिसमें 15000 करोड़ रुपये के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा– मुंबई
- पत्रिका 'नेचर क्लाइमेट चेंज' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने से आगामी 50 वर्ष में जितने प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ने की आशंका है–1700
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार इस राशि का सिक्का जारी किया गया– 20 रु.
- दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया कॉमन मोबिलिटी एप्प – One Delhi
- इन दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई है – 07 मार्च
- मेनका गांधी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपब्धियों को किस नाम से चलाए गये अभियान के तहत सम्मानित किया गया – वेब वंडर वुमेन
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थलसेना की जितने शाखाओं में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन दिया जाएगा–10
- वह देश जिसके साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2019 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया है– अमेरिका
- फोर्ब्स के मुताबिक, फेसबुक को–फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को पछाड़कर 21 वर्षीय जिस देश की टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं– अमेरिका
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब जितने लोगों की मौत हो रही है–800
- पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलनेवाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर जितने महीने का कर दिया है–3 महीना
- वह राज्य जिसमें हाल ही में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है –असम
- केंद्र सरकार ने इन्हें हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर–कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है –हसमुख अधिया
- वह विभाग जिसके तहत केंद्र सरकार ब्वे की गैर–प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेज़ी लाने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई गई है – DIPAM
- वह राज्य जिसने विश्वक बैंक के साथ व्यबय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ता क्षर किए –छत्तीसगढ़
- उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए जिस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं – विश्व बैंक

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- मुख्यमंत्री जयराम ने हिमाचल के किस क्षेत्र से प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की शुरूआत की– धर्मशाला से
- बाबा भूतनाथ मंदिर कहां है– मंडी में
- मंडी जिला के सूरजमणि किसके लिए प्रसिद्ध है– शहनाईवादक। इनको अमेरिका की एक संस्था ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है
- मंडी जिला के प्रसिद्ध देवता देव हुरंग नारायण के वजीर का दर्जा किस देवता को प्राप्त है–चौहारघाटी के प्रमुख देवा देवपाशा कोटजी
- हिमाचल प्रदेश में कितने नए अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे–10
- हिमाचल परिवहन विकास एवं रोड सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है– परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है– 18 से 40 वर्ष
- सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के 2019–20 के चुनाव 2019–20 के चुनाव में चेयरमैन बनाया गया है– हरीश अग्रवाल को चेयरमैन व ले. कर्नल शैलेष पाठक को वाइस चेयरमैन
- शिमला–चंडीगढ़ शिमला के लिए हैली टैक्सी की शुरूआत 28 फरवरी को कहां से शुरूआत की गई – जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा शिमला
- उड़ान से योजना किस कंपनी की सहायता से चलाई जाएगी– पवन हंस लिमिटेड
- हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं– 4 सीटें
- अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है– कबड्डी
- हिमाचल के कौन से खिलाड़ी पूर्व ओलंपियन हॉकी टीम के भारतीय कप्तान रह चुके हैं– पदम श्री चरणजीत सिंह
- विकास ठाकुर का संबंध किस खेल से है– अंतराष्ट्रीय भारातोलक से
- सिटाके मशरूम से बनाया गया कैप्सूल किस विटाममिन की कमी को पूरा करता है– विटामिन डी
- 30 जनवरी 2019 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ– जतोग कैंट को जबकि यूपी का मेरठ कैंट पहले स्थान पर रहा
- केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है– एसजेवीएनएल
- सरदार वल्लभभाई क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई– मंडी
- आयुष्मान भारत योजना की चुनौतियों को लेकर तैयार की गई प्रेजेंटेशन में डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडीकल कॉलेज अस्पताल टांडा के किस प्रशासनिक अधिकारी को स्कॉच ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है– डाक्टर विक्रांत
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुतबिक हिमाचल प्रदेश के कितने शहर भयंकर प्रदूषण की चपेट में है– 7, बद्दी, नालागढ़, परवाणु, परवाणु, पावंटस साहिब, कालाअंब, सुंदरनगर और डमटाल
- हिमाचल के किस जिले में पीजीआई सेंटर खोला जा रहा है–ऊना
- हिमाचल प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब स्थापित की गई– 36
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए नई आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है–18 से 45 वर्ष

शिक्षा लोन योजना : ऑनलाइन आवेदन एवं एप्लीकेशन फार्म... जाने पूरी प्रक्रिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ऐजुकेशन लोन योजना - अधिकतर देखा जाता रहा है की कई प्रतिभाशाली छात्र पैसे न होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते है देश में इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एजुकेशन लोन योजना को शुरू करने का एलान किया था । इस योजना के अंतर्गत, अब कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है परन्तु वह पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाता है अब वह छात्र भी अपनी शिक्षा के लिए लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है । हम इस लेख में विस्तार से बताएंगे की कैसे आप इस अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते है । इसके लिए आपको कही जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योकि आप इस योजना के अंतर्गत, अगर लोन लेना चाहते है इसके लिए घर बैठे–बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

एजुकेशन लोन योजना

यदि आप इस योजना के अंतर्गत, भारत में पढ़ाई करने के लिए लोन लेना चाहते है तो आपको इसमें 10 लाख रूपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है इसके साथ ही अगर कोई छात्र विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए इस योजना के अंतर्गत, 20 लाख रूपये की धनराशि का लोन दिया जाएगा । जिससे वह अपनी शिक्षा सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ।

डिजिटल सेवा पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण

ज़रुरी पात्रता व एजुकेशन लोन योजना

यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपका भारत का निवासी होना अनिवार्य है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते है ।

इसके साथ ही आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।

इसके अलावा, आप केवल मान्यता प्राप्त वेबसाइट से ही इस योजना के लिए आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की पहले आपका किसी भी बैंक में पैसा बकाया न हो ।

दो पासपोर्ट साइज फोटो
उम्मीदवार–माता–पिता–अभिभावक तथा गारंटर (जो भी लागू हो) का पहचान पत्र (आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड) पासपोर्ट अथवा बिजली या टेलीफोन बिल की फोटो कॉपी गारंटर से जुड़े विवरण (जब ऋण की राशि 4 लाख रुपये से अधिक हो)
ऋणकर्ता–गारंटर की आय का प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र
उत्तीर्ण परीक्षा मार्कशीट
प्रवेश प्रमाणपत्र
व्यय के विवरण तथा कोर्स की अवधि
कॉलेज–विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण–पत्र
कहाँ से प्राप्त करें लोन

निम्नलिखित बैंक इस योजना के अंतर्गत आपको लोन देते है जैसे कि

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : www.statebankofindia.com
इलाहाबाद बैंक : www.allahabadbank.com
पंजाब नेशनल बैंक : www.pnbindia.in
बैंक ऑफ इंडिया : www.bankofindia.com
केनरा बैंक : www.canarabank.com
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया : www.centralbankofindia.co.in
एचडीएफसी बैंक : www.hdfcbank.com
जम्मू–कश्मीर बैंक : www.jkbank.net
ऐक्सिस बैंक : www.axisbank.com
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला :www.sbp.co.in

कैसे मिलता है बैंक से लोन

बैंक एजुकेशन लोन देने से पहले उसकी रिपेमेंट सुनिश्चित करता है। आमतौर पर लोन उसे ही दिया जाता है, जो इसे वापस करने की क्षमता रखता है । रिपेमेंट लोन लेने वाले स्टूडेंट के अभिभावक कर सकते हैं या फिर लोन लेने वाला स्वयं पढ़ाई खत्म करने के बाद रिपेमेंट कर सकता है । लोन लेने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ती है । गारंटर लोन लेने वाले का अभिभावक या फिर रिश्तेदार हो सकते हैं।

एजुकेशन लोन का दायरा

बैंक किसी भी कोर्स के लिए होने वाले खर्चों की पूर्ति करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराता है । एजुकेशन लोन के दायरे में देश और विदेश में पढ़ाए जाने वाले कोर्स शामिल होते हैं । आप चाहें, तो किसी के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं । भारत में बारहवीं की स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पी.एच.डी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, लॉ, डेंटल, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के कम्प्यूटर कोर्स, आईसीडब्लूए, सीए आदि जैसे कोर्सों के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं । यदि आप विदेश में पढ़ाई की चाहत रखते हैं, तो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसीए, एमबीए, एमएस आदि के लिए भी एजुकेशन लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं ।

किसके लिए मिल सकता है लोन

स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की फीस, परीक्षा, लाइब्रेरी और लेबोरेटी की फीस, किताबें, इक्विपमेट, इंस्ट्रूमेंटस, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए,विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च, रास्ते का खर्च, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस इत्यादि।

लोन लेने से पहले ध्यान दें

मंदी के कारण आजकल मार्केट की स्थिति काफी बेहतर नहीं है। ऐसे में जान लें कि आप जो लोन लेने जा रहे हैं। उसकी रिपेमेंट सही समय पर हो जाए। इसलिए लोन उतना लिया जाए, जितना आप उठा सकें। नौकरी लगने के बाद रिपेमेंट के ऑपशन पर विचार करने से पहले सभी विकल्पों और अच्छी–बूरी सभी प्रकार की संभावनाओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाना चाहिए । बेशक बाजार की मांग और आपूर्ति का इस सेक्टर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, लेकिन फ्लोटिंग रेट का असर जरूर पड़ता है । विशेषकर लम्बी अवधि के लोन फ्लोटिंग रेट से प्रभावित होते हैं।

लोन चुकाने के अवसर

बैंक अन्य लोन की तरह ही एजुकेशन लोन पर भी ब्याज वसूलता है, लेकिन यह वसूली करने के लिए उसके पास मुख्य रूप से तीन विकल्प हैं । इनमें एक आकर्षक जरिया है मोरेटोरियम पीरियड जिसे रिपेमेंट हॉलीडे भी कहा जाता है । इसमें विकल्प होता है कि लोन लेने वाला इसकी रिपेमेंट जिस कोर्स में एडमिशन लिया गया है, उसकी समाप्ति के बाद कर सकता है।

एजुकेशन लोन आसानी से स्वीकृत कराने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?

स्टूडेंट को चाहिए कि वे लोन से संबंधित जो विवरण और दस्तावेज दे रहे हैं, वे पूरी तरह सही हों और बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों । साथ ही, कोर्स के दौरान कितना खर्च आ सकता है, उसका भी विवरण देना चाहिए।

एजुकेशन लोन के रिपेमेंट की प्रक्रिया क्या है?

कोर्स के दौरान पहले साल उपयोग किए गए लोन का सिम्पल इंटरेस्ट ही अदा करना होता है । लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद रिपेमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के पांच वर्षो में पूरा पेमेंट

करना होता है ।

शिक्षा लोन के ये पांच फायदे आपको हर हाल में मालूम होने चाहिए

शिक्षा पर लगने वाला खर्च हर साल महंगा होता जा रहा है । बच्चों की पढ़ाई के लिए माता–पिता पैसे की जुगाड़ में सोने में या फिक्स्ड एसेट में निवेश करते हैं । हालांकि, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर का कहना है कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए माता–पिता एजुकेशन लोन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बैंक या एनबीएफसी (गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी) से एजुकेशन लोन मिलता है ।

ज्यादा बचत:

ऐजुकेशन लोन लेने के बाद आप बिना किसी व्यवधान के अपनी कमाई में से बचत को जारी रख सकते हैं, जिससे आगे आपकी किसी भी वित्त जरूरतों की पूर्ति हो सकती है । आप चाहें तो बच्चों की शादी, घर खरीदने में अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकते हैं । इससे यह होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

कवरेज:

ऐजुकेशन लोन से न केवल आप अपनी कोर्स का फीस भर पाएंगे बल्कि, यह आपके अन्य खर्चे जैसे– हॉस्टल खर्च, परीक्षा फीस, लाइब्रेरी चार्ज, लैब फीस में भी काम आएगा । लोन का इस्तेमाल आप किताब का खर्च, यात्रा व्यय आदि में भी कर सकते हैं ।

टैक्स में फायदा:

आयकर अधिनियम की धारा 80 ई के तहत, एजुकेशन लोन पर भुगतान की जाने वाली पूरी राशि ब्याज आयकर कटौती के लिए मान्य है। आयकर कटौती का दावा आठ साल तक किया जा सकता है ।

मोरेटोरियम पीरियड:

मोरेटोरियम पीरियड लोन टाइम के समय उधारकर्ता को दी गई अवकाश अवधि की तरह है । इस अवधि में उधारकर्ता को लोन चुकाने से छूट मिलती है । ऐजुकेशन लोन के मामले में, उधारकर्ता को कोर्स पूरा होने की तारीख से 6 महीने से 1 वर्ष तक के लिए छूट मिलती है, इससे लोन लेने वाले को अच्छी नौकरी तलाशने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है

क्रेडिट की जानकारी:

अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसका पुनर्भुगतान समय पर करते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी और आगे भी आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

ये भी जाने

ऐजुकेशन लोन के रूप में आपको ऐसी परिस्थितियों में काफी मदद मिलती है। यह लोन आपकी जरूरत और उपलब्ध रकम के बीच की खाई को भरता है एक अध्ययन के अनुसार पढ़ाई का खर्च सालाना 15 फीसदी की दर से बढ़ रहा है । इस समय अगर पढ़ाई का खर्च 2.5 लाख रुपये है तो 15 साल बाद एमबीए करने में 20 लाख रुपये खर्च होंगे ।

अगर कोई पैरेंट अभी से 15 सालों तक हर महीने 2000 रुपये का निवेश करता है और इस पर औसत रिटर्न 12 फीसदी मान लें तो वह करीब 9.5 लाख रुपये ही जोड़ पायेगा ।

एजुकेशन लोन में क्या कवर होता है?

इसमें कोर्स की बेसिक फीस और कॉलेज के दूसरे खर्च (रहने, एग्जाम और अन्य) कवर होते हैं । लोन के लिए कौन अप्लाय कर सकता है? पढ़ाई करने वाला छात्र मेन बॉरोअर होता है । उसके पैरेंट्स, या भाई–बहन को बॉरोअर हो सकते हैं ।

लोन किसे मिल सकता है?

भारत में पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र लोन ले सकते हैं। दोनों जगह पढ़ाई के लिए लोन की रकम अलग हो सकती है और यह बैंक पर भी निर्भर करता है ।

लोन के तहत किस तरह के कोर्स आते हैं?

लोन लेकर फुल टाइम, पार्ट टाइम या वोकेशनल कोर्स किये जा सकते हैं । इसके अलावा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर आदि में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लोन लिया जा सकता है ।

हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

'हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना' हिमाचल राज्य के मेधावी छात्रों के लिए चलाई जा रही हैं। सरकार का मानना हैं कि राज्य में बहुत से ऐसे गरीब होनहार छात्र हैं जो पैसों की कमी के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं। आजकल के समाज में कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज़रुरी हो गया हैं। लेकिन गरीबी के कारण कई छात्र लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं।

इसके लिए सरकार ने 'मुफ्त डिजिटल लैपटॉप योजना' को शुरू किया हैं । मुफ्त लैपटॉप योजना में सरकार राज्य के मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया।

मुफ्त डिजिटल लैपटॉप योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कैसे भरें

इस योजना के लिए क्या पात्रता होगी, किन– किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी, इसकी हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे ।

मुफ्त लैपटॉप योजना हिमाचल के लिए योग्यता

हिमाचल प्रदेश में 'राजीव गांधी मुफ्त लैपटॉप योजना' का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास यहां बताई जा रही योग्यता का होना जरुरी हैं। इसके योग्य व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं।

- आवेदक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- राजीव गांधी मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ करने के लिए छात्र को होनहार होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ही प्राप्त कर सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक छात्र के पास हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं।
- आवेदककर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य हैं।
- छात्र के पास उस कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमे वह पढ़ रहा हो।

हिमाचल प्रदेश मे मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो : महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना शुरू की गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों का कल्याण है। अनाथ बच्चा वह है जिसका माता पिता मृत, अज्ञात है, या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, इस तरह के बच्चों की देखभाल और रखरखाव के लिए यह योजना हैं। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार को मुफ्त आश्रय, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और पेशेवर मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। राज्य में सभी अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए, बाल उधार योजना का हिस्सा बनने और योजना द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्तेदार मदत करें। महिलाओं और बाल विकास कार्यालय में अधिक विवरण और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लाभ:

अनाथ बच्चों को कई लाभ प्रदान करने के लिए बाल कल्याण योजना

इस योजना के तहत, हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, खाना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें

- हिमाचल प्रदेश के अनाथ लड़की या लड़के

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेज:

- पहचान प्रमाण

- आवेदन प्त्र (कार्यालय में उपलब्ध)
- निवासी प्रमाण

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अब किसान अपनी पसंद की कंपनी से करवा सकेंगे सोलर फेंसिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो : फसल को जंगली जानवरो से बचाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अब किसान अपनी पसंद की कंपनी से सोलर फेंसिंग करवा सकेंगे। जिसके लिए सरकार ने 32 विभिन्न कंपनियों को सोलर फैंसिंग के लिए मान्यता दी है। अगर किसानों को एक कंपनी का प्रोजैक्ट पसंद नही आता है तो वह दूसरी कंपनी से सोलर फैंसिंग लगवा सकता है ।

वहीं अगर किसान इसी सोलर प्लांट प्रोजैक्ट को सामूहिक रूप से लगवाते हैं तो इन्हें 85 फीसदी तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। जबकि एकल किसान को इस योजना के तहत सोलर फैंसिंग लगाने पर 80 फीसदी अनुदान का प्रावधान है।

इच्छुक किसान अपनी जिला कृषि खंड में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब यह योजना पूर्व सरकार में शुरू की गई थी तो इस पर किसानों को 60:40 के अनुपात में अनुदान किसानों को दिया जा रहा था। लेकिन इस अनुपात में किसानों को इसका खर्च काफी ज्यादा पड़ता था। जिससे किसानों ने इस योजना से किनारा ही कर लिया। जिसके बाद इस योजना पर 80 फीसदी का अनुदान कर दिया गया।

सोलर प्लांट में भी तकनीकी दिक्कतें आने के बाद किसान अब सोलर फैंसिंग के स्थान पर कांटेदार तार या जालीदार जाल लगवाने की मांग करने लगे हैं। किसान वर्ग का मानना है कि सोलर प्लांट योजना उत्पाती जानवरों के लिए उचित नही है। इसमें लगने वाली तार को जंगली जानवर एक ही झटके में तोड़ देंगे।

वहीं अगर इस सोलर फैंसिंग का घास टच करता है तो इसमें लगा करंट काम नही करेगा। जिससे बरसाती दिनों में इसका रखरखाव काफी मुश्किल हो सकता है। मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना के तहत सोलर प्लांट में तार लगाने के तीन अलग–अलग प्रोजैक्ट हैं। जिनमें पांच फीट, सात फीट व नौ फीट ऊंचाई के प्रोजैक्ट हैं। अब यह किसान पर निर्भर करता है कि वह कौन सा प्रोजैक्ट लगवाना चाहता है, किसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है।

इस योजना के तहत खेत का चारो तरफ से कवर करने के लिए 1500 मीटर रनिंग में तार लगाई जाएगी। 1500 मीटर तार को करंट देने के लिए एक सोलर प्लांट भी स्थापित होगा। इसी सोलर प्लांट से खेत के चारों तरफ लगाई गई तार में करंट दौड़ेगा।

सोलर फैंसिंग में इसके आसपास हर समय घास कटा हुआ चाहिए। 32 कंपनियों को सोलर फैंसिंग लगवाने के लिए सरकार ने मान्यता दे दी है। किसान अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी का प्रोजैक्ट खेत में लगवा सकता है।

घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है। जंगली और बेसाहरा जानवर किसानों के लिए विकराल समस्या बने हुए हैं। फसलों को नुकशान पहुंचाने के चलते किसान खेतीबाड़ी से छोड़ने को मजबूर होने लगे थे। किसानों द्वारा समय–समय पर प्रदेश सराकर के समक्ष भी यह गंभीर समस्या लाई जा रही थी । प्रदेश सरकार ने किसानों के फसलों को बचाने और प्रदेश की उपजाउ भूमि को हराभरा रखने के लिए महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना तैयार की जिससे किसानों के खेतों को बाड़ लगाकर फसलों को बचाया जा सके । सरकार ने खेतों की बाड़ बंदी के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में सौर उर्जा आधारित बाड़ लगाने की योजना तैयार की। इस योजना में किसानों को सौर बाड़ 80 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाई गई। सौर बाड़ में हल्का सौर आधरित करंट होता है और जैसे ही कोई जानवर इसके संपर्क में आता है उसको हल्का करंट लगता है और जानवर यहां से भाग जाता है। करंट हल्का होने के चलते इंसान के इसके संपर्क में आने से उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सौर उर्जा आधारित बाड़ के काफी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए यह बाड़ लगाने के लिए आगे आने लगे हैं। पालमुपर उपमण्डल के गांव गदियाड़ा, डाकघर सल्याणा के भूतपूर्व सैनिक कै0 प्यार चंद लावारिश पशुओं के खौफ से लगभग अपने खेतों की बीजाई का कार्य छोड़ चुके थे। विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए विभाग समय–समय पर जागरूकता कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

HP/129/SML/2019-2021

मिशन रीव में स्थाई आय कमाने का बेहतरीन अवसर

एनएसडीसी से प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण का भी मौका

VACANCIES WITH MISSION RIEV THROUGH NSDC ALIGNED TRAININGS

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

All Districts Himachal Pradesh

Position	Service Associates (To undertake 3 Service Segment Roles)
Present Priority	3 in each Gram Panchayat: Likely to touch 10 numbers in each GP
Qualifications	Minimum Graduate or Equivalent
Age	20-35 Year
Technical Requirements	Basic Knowledge of IT-Own Laptop or Tablet Mandatory
Training Period	1st April to 30th April 2019
Training Job Role	IT and Retail (Terms & Conditions apply)
Training Certification	NSDC Certification (IIRD being NSDC Partner) T & C Apply
Remuneration Range	Rs. 10,000- Rs. 18,000 (Subject to work done as per Dashboard)
Application Fee	Rs. 300/-
Last Date	30.03.2019 For 1st lot Training in April & Deployment in May 2019 April's applicants shell get training opportunity in may & deployment in June 2019 and so on until all vacancies are filled.

Please Visit :
missionriev.in
Ph. 0177-2844073 / 2843528
Email : admin@missionriev.in

Please Note: Mission RIEV is a collaborative initiative under the aegis of IIRD and the vacancies are nowhere linked to the Government. As Middion RIEV is a self-revenue generating model, the interested candidates are advised to go through the terms & conditions carefully before applying. For details and online application.

MISSION RIEV SECRETARIAT, IIRD COMPLEX, BYE PASS ROAD, SHANAN, SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH

आईआईआरडी शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए मिशन रीव के तहत आय कमाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। मिशन रीव संस्करण –2 के पहले चरण में विभिन्न पंचायतों में सर्विस एसोसिएट की भर्ती की जा रही है। इसके लिए 25 मार्च 2019 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले चरण में की जा रही भर्तियों में शिमला, ऊना, चंबा और बिलासपुर में सर्विस एसोसिएट की भर्ती की जा रही है जबकि बाकि जिलों में भी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्येक पंचायत में तीन सर्विस एसोसिएट की भर्ती की जाएगी और इन्हें आईआईआरडी की ओर से एनएसडीसी के तहत 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक एक माह का विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद एनएसडीसी की ओर से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आईआईआरडी को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से साझेदार के तौर पर कौशल विकास के लिए अधिकृत किया गया है।

बहरहाल, सर्विस एसोसिएट्स के पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नात्तक अथवा उसके समकक्ष कोर्स व डिप्लोमा निर्धारित की गई है। मिशन संस्करण –2 के तहत सभी कार्य ऑनलाइन ही किए जाने हैं, ऐसे में आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होने के साथ ही अपना खुद का लैपटॉप अथवा टैबलेट होना अनिवार्य है।

चयनित होने पर कार्य के हिसाब से सर्विस एसोसिएट्स के पास अपने काम के आधार पर प्रतिमाह 10 हजार से 18 हजार तक आय कमाने का विकल्प रहेगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क मात्र 300 रूपये प्रति आवेदक निर्धारित किया गया। आवेदन करने के बाद किसी भी स्थिति में शुल्क वापिस नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें: यह प्रक्रिया पूरी तरह आईआईआरडी शिमला के तहत पूरी की जाएगी तथा इसका संबंध किसी भी तरह से सरकारी प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है। आईआईआरडी पूरी तरह एक निजी संस्था है।

आईआईआरडी और एनएसडीसी में साझेदारी

आईआईआरडी ने हाल ही में एक और मुकाम हासिल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानि एनएसडीसी के साथ साझेदारी कर हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर खोल दिए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी के बाद आईआईआरडी प्रदेश के युवाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न ट्रेड में कला–कौशल प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एनएसडीसी की ओर से आईआईआरडी युवाओं/ प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी करेगा। पहले यह प्रक्रिया साधारण नहीं थी क्योंकि एनएसडीसी से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई तरह की औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता था। आईआईआरडी इसे हिमाचल में अब सरल करने के लिए अधिकृत है ।

क्या है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानि एनएसडीसी :

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (छंजपवदंस ैपसस क्मअमसवचउमदज ब्चवतंजपवद) कौशल विकास को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है । यह एक निजी और सरकारी निकाय में कार्य करने वाली ईकाई है। विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में एनएसडीसी का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एनएसडीसी 21 से भी अधिक क्षेत्रों में सेवाऐं दे रही है । एनएसडीसी उन निजी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग करती है जो कौशल विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर ही है। इसी के तहत आईआईआरडी के साथ भी साझेदारी हुई है ।

कौशल विकास में आईआईआरडी :

आईआईआरडी एक लंबे समय से कौशल विकास में अपनी सेवाएं प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर देश के अन्य राज्यों में दे रहा है । विभिन्न ट्रेड एवं श्रेणियों में आईआईआरडी ने कला कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर हज़ारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए है । इसी के चलते अब एनएसडीसी ने आईआईआरडी की इन सेवाओं के कारण साझेदारी का प्रमाण पत्र दिया है ।

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स उत्कृष्ठ गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रूपये, छः माह के लिए 250/रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

HPKVN | Skill India कौशल भारत-कुशल भारत | N·S·D·C National Skill Development Corporation Transforming the skill landscape | PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास से आएगा निखार खुलेंगे रोज़गार के द्वार

भारत सरकार का उपक्रम

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास प्रशिक्षण का सुनहरा मौका

आईआईआरडी और एचपीकेवीएन के संयुक्त तत्वाधान में

प्रशिक्षण पूरा करने पर अभ्यर्थी को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए कम ब्याज दरों पर बिना गारन्टी के मुद्रा लोन दिलवाने की भी व्यवस्था है

कौशल हिमाचल समृद्ध हिमाचल

ज़िंदगी जियें-नशे को नहीं
स्वस्थ एवं नशामुक्त हिमाचल बनाने में दें सहयोग

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर Institute for Integrated Rural Development

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006
Phone No. : 0177 2640761, Mob. 91311 24634, 85280 89637
Email : info@missionriev.in, Web : www.missionriev.in

कि दुनिया देखती रह जाए